

प्रेरणा विचार

RNI No. : UPHIN/2023/84344 ₹: 30/-

मासिक

वैशाख-ज्येष्ठ, विक्रम संवत् 2083 (मई-2026)

पृष्ठ-36, गौतमबुद्धनगर से प्रकाशित



कॉर्पोरेट

मतांतरण का नया रणक्षेत्र

मई-2026

रविवार	सोमवार	मंगलवार	बुधवार	गुरुवार	शुक्रवार	शनिवार							
दशै अष्टमिवाचनं होमकर जयंती, अधिक मास मई ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा	31				बृह पूरणिमा, श्री कूर्म जयंती	1	श्री नारद जयंती	2					
ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वितीया	3	ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष तृतीया	4	श्री गणेश चतुर्थी व्रत	5	ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष षष्ठी	8	ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा	9				
ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अष्टमी	10	ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष नवमी	11	ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष दशमी	12	ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी	15	ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या	16				
अधिक मास प्रारंभ	17	अधिक मास	18	अधिक मास	19	श्री गणेश चतुर्थी व्रत, अधिक मास	20	अधिक मास	23				
ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा	ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वितीया	ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया	ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्थी	ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पंचमी	ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष षष्ठी	ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सप्तमी	ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी	ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष नवमी	ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी				
अधिक मास	24	पार्वीवाचनं श्री गंगा जयंती	25	श्री गंगा दशहरा, अधिक मास	26	वृषभोत्थ एकादशी, अधिक मास	27	श्री सायंबकार जयंती, प्रदोष व्रत	28	अधिक मास	29	अधिक मास	30
ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी	ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष नवमी	ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी	ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी	ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वादशी	ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी	ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी							

मई-2026 त्यौहार वैशाख-ज्येष्ठ, 2083

01 शुक्रवार	कूर्म जयन्ती, बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, अन्वाधान	02 शनिवार	नारद जयन्ती, इष्टि	05 मंगलवार	एकदन्त संकष्टी
13 बुधवार	अपरा एकादशी	14 बृहस्पतिवार	गुरु प्रदोष व्रत	15 शुक्रवार	वृषभ संक्रान्ति
16 शनिवार	वट सावित्री व्रत, शनि जयन्ती, दर्श अमावस्या, अन्वाधान, ज्येष्ठ अमावस्या	17 रविवार	इष्टि, अधिक चन्द्र दर्शन	25 सोमवार	गंगा दशहरा
27 बुधवार	पद्मिनी एकादशी	28 बृहस्पतिवार	गुरु प्रदोष व्रत	31 रविवार	ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा, अन्वाधान

प्रेरणा विचार

वर्ष -4, अंक - 05

RNI No. UPHIN/2023/84344

संरक्षक

अनिल त्यागी

प्रबंध निदेशक

बिजेन्द्र कुमार गुप्ता

सलाहकार मंडल

श्याम किशोर

संपादक

डॉ. मनमोहन सिंह शिशौदिया

कार्यकारी संपादक

डॉ. प्रियंका सिंह

प्रबन्ध संपादक

मोनिका चौहान

अध्यक्ष प्रीति दादू की ओर से मुद्रक/प्रकाशक
डॉ. अनिल त्यागी द्वारा चंद्र प्रभु ऑफसेट
प्रिंटिंग वर्क प्रा. लि. नोएडा से मुद्रित तथा
प्रेरणा भवन, सी-56/20, सेक्टर-62
नोएडा, गौतमबुद्धनगर से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

प्रेरणा शोध संस्थान न्यास

प्रेरणा भवन, सी-56/20, सेक्टर-62,

नोएडा - 201309

दूरभाष : 0120 4565851

मोबाइल : 9354133708, 9354133754

ईमेल : prernavichar@gmail.com

वेबसाइट : www.pernasamvad.in

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्ति
विचार लेखकों के अपने हैं। संपादक का
उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
सभी विवादों का निपटारा नोएडा की सीमा
में आने वाली सक्षम अदालतों/फोरम में
मान्य होगा।

संपादक

इस अंक में



कॉर्पोरेट तक पहुंचा मतांतरण और
गजवा-ए-हिंद का रणक्षेत्र -05



नारी शक्ति वंदन अधिनियम
शिक्षा से आगे, अब सत्ता तक -11



बच्चों की छुट्टियां
कैसे दिलचस्प बनाएं-20



सांस्कृतिक और आध्यात्मिक
उत्सवों से भरपूर मई - 28

परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक सफलता	07
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट	08
कॉर्पोरेट जिहाद.....	14
श्रीनगर में 36 वर्ष बाद खुला रघुनाथ मंदिर.....	16
गर्म हवा का गुंबद बढ़ाता धरती का तापमान.....	18
काशी में विश्व की प्रथम 'विक्रमादित्य वैदिक घड़ी' हुई स्थापित	22
श्रीसेतु मन्दिरम की बारी सन्निकट.....	24
बच्चों के मानसिक विकास पर वायु प्रदूषण का मंडराता गंभीर खतरा.....	26
न्यूज स्टोरी.....	30
कुलदेवता.....	34

कॉर्पोरेट जिहाद

इतिहास गवाह है कि सनातन मूल्यों एवं संस्कारों के अनुरूप, भारत न कभी आक्रांता रहा और न ही मतांतरण का पोषक। परंतु विडंबना है कि वह सदियों से विदेशी आक्रमणों तथा आक्रान्ताओं द्वारा कराए गए मतांतरण का शिकार रहा है। इसके मूल में भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता को नष्ट कर उन्हें ऐसे मतों से जोड़ना रहा जिनके श्रद्धा केंद्र भारत से बाहर हों, जिससे भारत की एकता को खंडित किया जा सके और अपने अधीन रख राज्य किया जा सके। इसके लिए योजना बनाने और योजना के क्रियान्वयन हेतु आर्थिक सहायता के साथ ही रणनीतिक सहायता मिलती रही है। मतांतरण राष्ट्र की सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान के लिए खतरा है और राष्ट्रान्तरण की तरह ही है।

लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, जिम जिहाद के बाद अब सामने आया है कॉर्पोरेट जिहाद। यह मामला तब संज्ञान में आया जब नासिक स्थित टीसीएस कंपनी में कार्यरत महिला कर्मचारियों के एक समूह की आदतों, वेशभूषा, पूजापाठ और रहन-सहन के तरीकों में बदलाव देखा गया। उनके द्वारा रोजे रखे जाना, नमाज पढ़ा जाना आदि, जिनकी सत्यता वहां के सीसीटीवी से प्रमाणित हुई है। इस संबंध में 9 प्राथमिकी दर्ज होने का बाद प्रकरण की गंभीरता के मद्देनजर इसे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एन.आइ.ए.) को सौंप दिया गया है। प्रकरण की पीडिताओं को प्रमोशन, अच्छे अवसर आदि का आश्वासन देकर कार्यालय परिसर में नमाज पढ़ने तथा गौमान्स आदि के सेवन के लिए प्रेरित किया जाता था। ये गैंग हिन्दू देवी-देवताओं पर अश्लील टिप्पणी कर, लड़कियों को पिकनिक स्पॉट ले जाकर, प्रलोभन देकर, अपने पंथ को महिमा

मंडित कर उनका मतांतरण कराते हैं। यह नया स्वरूप भले ही अभी उजागर हुआ हो, भारत में मतांतरण की प्रक्रिया इस्लाम और ईसाइयत के आगमन के साथ ही शुरू हो गई थी। ईसा मसीह के शिष्य सेंट थॉमस द्वारा 52 ईस्वी में केरल के तट पर पहुंचने के बाद दक्षिण भारत में अनेकों चर्चों की स्थापना हुई। तत्पश्चात यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के दौरान, विशेषकर पुर्तगालियों और अंग्रेजों के समय, मिशनरियों द्वारा मतांतरण को बढ़ावा मिला। वहीं भारत में इस्लाम का प्रसार 8-वीं शताब्दी में मुहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से शुरू हुआ, सूफ़ी संतों की गतिविधियों और मुस्लिम शासकों के प्रभाव में तेजी से बढ़ा, और आज तक जारी है। मतांतरण के ऐसे प्रयासों को पश्चिमी तथा अरब देशों से भी आर्थिक मदद मिलती रही है।

कॉर्पोरेट जिहाद भारत के लिए एक नई चुनौती के रूप में उभरा है। ऐसी घटनाओं से उन माता-पिता का असहज होना स्वाभाविक है जिनकी बेटियां कॉर्पोरेट समूहों में कार्यरत हैं। यह सुनिश्चित करना होगा कि कहीं उन्हें यह न लगने लगे कि जैसे हर दफ्तर में मतांतरण के ठेकेदार बैठे हुए हैं। भारतीय कॉर्पोरेट पर इसका दुष्प्रभाव न हो इसके लिए ऐसे गिरोहों का उन्मूलन आवश्यक है। सरकार, कॉर्पोरेट और समाज को कुम्भकर्णी नदी से जागकर अन्दर द कार्पेट चल रहे इस जिहाद जैसे संगठित अपराध को जड़ से मिटाना होगा। तथाकथित कॉर्पोरेट संस्कृति में 'यत्र नार्थस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' को स्थापित कर, जिहादियों का सामना करने के लिए बेटियों को स्वयं सुरक्षा के गुणों से सम्पन्न कर उन्हें रणचंडी बनने के लिए तैयार करना होगा।

(समस्त संदर्भ स्रोतों के प्रति कृतज्ञता)

कॉर्पोरेट तक पहुंचा मतांतरण और गजवा-ए-हिंद का रणक्षेत्र धार्मिक परिवर्तन के रूप में एक विस्तृत विश्लेषण



डॉ. गायत्री दीक्षित
जेएनयू



आज कॉर्पोरेट जगत की चकाचौंध भरी दुनिया में एक नई और चिंताजनक कहानी लिखी जा रही है। मतांतरण अब सिर्फ पुराने गांवों या आदिवासी इलाकों तक सीमित नहीं रहा। यह एयर-कंडीशंड ऑफिसों, BPO यूनिट्स, लिंकडइन प्रोफाइल्स और 'वेलनेस सेशन' के नाम पर फैल रहा है। पहले यह आर्थिक या तकनीकी बदलाव था AI, क्लाउड, 5G अब खुलकर धार्मिक परिवर्तन यानी जबरन या प्रलोभन से कन्वर्शन का रूप ले चुका है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में यह सिर्फ आर्थिक मामला नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक रणक्षेत्र बन गया है। कुछ चर्चाओं में इसे गजवा-ए-हिंद के आधुनिक संस्करण से जोड़ा जा रहा है वह कथा जो कुछ हदीसों से निकली और पाकिस्तान आधारित समूहों द्वारा इस्तेमाल होती रही है। हम एक राजनीतिक विश्लेषक की नजर से देखें तो साफ दिखता है कि कॉर्पोरेट मतांतरण अब सिर्फ बिजनेस की भाषा में नहीं, बल्कि संस्कृति और पहचान की लड़ाई में बदल गया है। यह विश्लेषण तथ्यों, हालिया घटनाओं, डेटा और उदाहरणों के साथ देखेगा कि

कॉर्पोरेट में धार्मिक मतांतरण कैसे फैल रहा है, इसके दीर्घकालिक परिणाम क्या हो सकते हैं, इसे रोकने की चुनौतियां क्या हैं और पूरा मामला किस दिशा में जा रहा है।

कॉर्पोरेट में मतांतरण : धार्मिक परिवर्तन का नया और खतरनाक स्वरूप - भारत का IT सेक्टर FY26 में 315 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। NASSCOM के अनुसार 6.1 प्रतिशत की ग्रोथ के साथ यह पहली बार 300 बिलियन डॉलर के पार पहुंचा। AI सर्विसेज अकेले 10-12 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू दे रही हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मार्केट 2026 में 144.48 बिलियन USD का है और 2031 तक 304.86 बिलियन USD तक पहुंचने की उम्मीद है, CAGR 16.12 प्रतिशत के साथ। TCS, Infosys, Wipro जैसी कंपनियां AI, क्लाउड और 5G पर अरबों खर्च कर रही हैं। TCS अकेले FY26 में अपना AI रेवेन्यू 2.3 बिलियन USD तक ले गया, Q4 में 17.3 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। कंपनी ने 5,500 AI प्रोजेक्ट्स पूरे किए और 450,000 से ज्यादा कर्मचारियों को GenAI ट्रेनिंग दी। लेकिन

इस तकनीकी चमक की आड़ में कुछ और हो रहा है। DEI पॉलिसी, विविधता भर्ती और सांस्कृतिक अनुकूलन के नाम पर हिंदू कर्मचारियों पर दबाव, हलाल सर्टिफिकेशन, प्रेयर रूम और जबरन कन्वर्शन के आरोप लग रहे हैं। TCS के नासिक BPO यूनिट का मामला सबसे ताजा और चौंकाने वाला उदाहरण है। मार्च-अप्रैल 2026 में नासिक पुलिस में 9 FIR दर्ज हुईं। आठ हिंदू महिलाएं और एक पुरुष कर्मचारी जिन पर ये गंभीर आरोप लगे हैं, वे TCS नासिक BPO यूनिट में काम करते थे। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ, स्टॉकिंग की गई, ग्रोपिंग की गई, हिंदू देवताओं का अपमान किया गया, नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया गया, बीफ खिलाने की कोशिश की गई और सबसे गंभीर आरोप ये था कि जबरन इस्लाम में परिवर्तन की कोशिश की गई।

मुख्य आरोपी निदा खान है जो कि 26 साल की प्रोसेस एसोसिएट (टेलीकॉलर)। पुलिस और SIT ने उसे "क्रिमिनल कॉन्सिपेरेसी" का किंगपिन या मास्टरमाइंड बताया। निदा हिंदू लड़कियों को वीकेंड

पार्टीज, होटल और रिसॉर्ट में बुलाती। पहले दोस्ती, फिर रिलेशनशिप, फिर 'रुद्राक्ष' उतारकर इस्लाम अपनाने का दबाव। कई शिकायतकर्ताओं ने कहा कि निदा ने हिंदू देवताओं की पूजा पर आपत्ति जताई और 'सच्चा रास्ता' इस्लाम बताया। निदा खान फरार है और कोर्ट ने 20 अप्रैल को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और 27 अप्रैल को अंतिम सुनवाई तय की। उसके साथ डेनिश शेख, तौसीफ अत्तर, राजा मेमन, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, आसिफ अफताब अंसारी जैसे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक्सट्रीमिस्ट लिंक्स और फॉरेन फंडिंग की आशंका जताते हुए NIA, ATS और स्टेट इंटेलिजेंस को पत्र लिखा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई जिसमें जबरन धार्मिक परिवर्तन को 'टेररिस्ट एक्ट' घोषित करने की मांग की गई। TCS ने यूनिट के ऑपरेशंस सस्पेंड कर दिए, कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दिया और आंतरिक जांच पैनल बनाया। कंपनी का बयान है कि आंतरिक चैनल पर कोई शिकायत नहीं आई थी, लेकिन SIT जांच में 70 से ज्यादा ईमेल और चैट्स का जिक्र आया है जहां शिकायतें नजरअंदाज की गईं। यह सिर्फ एक यूनिट की घटना नहीं लगती, बल्कि 2022 से 2026 तक चल रहे सिस्टैमैटिक पैटर्न का हिस्सा है।

Infosys, Wipro, HCL जैसी कंपनियों में भी DEI के नाम पर टारगेटेड हायरिंग और सांस्कृतिक बदलाव के आरोप आए हैं। Reliance Jio की Intelligence Grid और Google-Meta JV के बीच हलाल पॉलिसी और प्रेयर रूम पर बहस चल रही है। BSE 500 कंपनियों में मुस्लिम कर्मचारी प्रतिनिधित्व सिर्फ 2.67 प्रतिशत है, जबकि आबादी में 14.2 प्रतिशत। Sachar Committee के आंकड़ों के मुताबिक मुस्लिम साक्षरता 59.1 प्रतिशत और ग्रेजुएट स्तर पर सिर्फ 4 प्रतिशत।

गजवा-ए-हिंद का कॉर्पोरेट रणक्षेत्र और इसके दीर्घकालिक परिणाम

गजवा-ए-हिंद कुछ हदीसों (Sunan al-Nasa'i, Musnad Ahmad) से जुड़ा शब्द है, लेकिन ज्यादातर विद्वान इन्हें दाइफ मानते हैं और eschatological (अंतिम समय संबंधी) बताते हैं। पाकिस्तानी ग्रुप इसे रिस्कूटमेंट टूल के रूप में इस्तेमाल करते रहे। अब नासिक मामले में BJP, शिवसेना और हिंदू संगठनों ने इसे 'Corporate Jihad' या 'Operation Ghazwa-e-Hind' कहा।

अगर यह धार्मिक मतांतरण अनियंत्रित रहा तो परिणाम गंभीर होंगे। वर्कफोर्स में डेमोग्राफिक शिफ्ट आएगी। IT और BFSI जैसे सेक्टरों में सांस्कृतिक एकरूपता टूटेगी। Pew Research के अनुसार 2050 तक भारत में मुस्लिम आबादी करीब 31 करोड़ पहुंच सकती है। हिंदू रिटेंशन रेट 99 प्रतिशत है, लेकिन प्रलोभन या जबरन कन्वर्शन से परिवार टूटेंगे, सोशल कोहेसन कमजोर होगा और गांव-शहर स्तर पर संघर्ष बढ़ेगा। आर्थिक रूप से प्रोडक्टिविटी प्रभावित होगी। **कॉर्पोरेट मतांतरण रोकने की चुनौतियां** : धार्मिक मतांतरण को रोकना आसान नहीं। पहली चुनौती कानूनी है। 12 राज्यों में एंटी-कन्वर्शन लहू हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में लागू करना मुश्किल। महाराष्ट्र का 2026 कानून 60 दिन पहले डिक्लेरेशन मांगता है, फिर भी HR 'व्यक्तिगत मामला' कहकर टाल देता है। बोझ साबित करने का आरोपी पर है। निदा खान गर्भवती होने का हवाला देकर बेल की कोशिश कर रही है। दूसरी चुनौती कॉर्पोरेट रेसिस्टेंस। ग्लोबल DEI पॉलिसी और वेस्टर्न क्लाइट्स के दबाव में कंपनियां विविधता बढ़ावा देती हैं। TCS जैसे जायंट AI पर 2.3 बिलियन USD रेवेन्यू बना रहे हैं, लेकिन जांच में देरी दिखती है। तीसरी चुनौती सबूत और जांच की। नासिक में 9 FIR और गिरफ्तारियों के बावजूद डिफेंस 'पर्सनल फॉलआउट' का हवाला दे रहा है। WhatsApp चैट, होटल बुकिंग और फॉरेन

लिंक्स की जांच ATS-NIA को भेजी गई, लेकिन प्रूफ इकट्ठा करना समय लेता है। चौथी चुनौती सामाजिक है 'सांप्रदायिक' लेबल लगने का डर। मीडिया और सेकुलर आवाजें अक्सर चुप रह जाती हैं जब पीड़ित हिंदू होते हैं। पांचवीं चुनौती स्कल गैप और हायरिंग। मुस्लिम कम्युनिटी में शिक्षा कम होने के बावजूद टारगेटेड रिस्कूटमेंट से नेटवर्क बन सकता है।

लड़ाई और समाधान क्या हो सकते हैं : कॉर्पोरेट मतांतरण अब धार्मिक परिवर्तन का रूप ले चुका है। TCS का AI रेवेन्यू 2.3 बिलियन USD और नासिक का कन्वर्शन सिंडिकेट दोनों एक साथ चल रहे हैं। निदा खान का फरार होना और ATS-NIA जांच इसे और गंभीर बनाती है। गजवा-ए-हिंद का रणक्षेत्र अब बोर्डरूम और ठच्च यूनिट्स तक पहुंच गया है। दीर्घकालिक परिणाम सांस्कृतिक क्षय, आर्थिक नुकसान और सुरक्षा खतरे के रूप में सामने आएंगे। इसे रोकने के लिए डेटा-ड्रिवन जांच, सख्त कानून लागू, POSH कमिटी को मजबूत करना, कैमरा सर्विलांस, रिलिजियस हेल्पलाइन और जागरूकता जरूरी है। जै जैसी कंपनियों ने आंतरिक गाइडलाइंस जारी की हैं, किसी भी प्रकार के जबरन कन्वर्शन या धार्मिक दबाव को डिस्पोजल का आधार बनाया गया है। लेकिन ऑफिस के बाहर चलने वाले ग्रुप और ऑनलाइन नेटवर्क पर नियंत्रण चुनौतीपूर्ण है।

भारत को 2030 तक AI से ट्रिलियनों का फायदा उठाना है, लेकिन धार्मिक मतांतरण की आड़ में हाइब्रिड खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। असली रणक्षेत्र अब आर्थिक विकास और सांस्कृतिक सुरक्षा का है। कंपनियां AI पर फोकस करें, लेकिन वर्कप्लेस को धर्म की लड़ाई का मैदान न बनने दें। समय आ गया है कि तथ्यों पर आधारित कार्रवाई हो, न कि सिर्फ चर्चा। जांच पूरी होने तक हर पक्ष का सम्मान जरूरी, लेकिन पीड़ितों की आवाज को दबने नहीं देना चाहिए।

परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक सफलता



मृत्युंजय दीक्षित
लेखक एवं साहित्यकार

पश्चिमी एशिया युद्ध और तनाव के मध्य भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। भारत ने तमिलनाडु के कलपक्कम स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र में क्रिटिकैलिटी प्राप्त कर ली है। अब रूस के बाद भारत दूसरा ऐसा देश बन गया है जहां ऑटो मोड में परमाणु चैन रिएक्शन प्रारंभ हो गया है। यह सपना महान वैज्ञानिक स्वर्गीय होमी जहांगीर भाभा का था जो अब पूर्ण हुआ है। वैज्ञानिकों की यह सफलता भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में सहायता देगी। यह 2070 के नेट जीरो लक्ष्य की ओर बड़ा कदम है।

अगर यह कार्य सफलता पूर्वक आगे बढ़ता रहा तो भारत जल्द ही पारंपरिक जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा बनाने की जगह स्वच्छ अक्षय ऊर्जा बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। भारत के 500 मेगावाट क्षमता वाले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के प्रथम क्रिटिकैलिटी स्तर पर पहुंचने के बाद सरकार ने कहा कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर उच्च तापीय दक्षता के साथ विश्वसनीय, कम कार्बन उत्सर्जन वाली बेस लोड बिजली आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नियंत्रित परमाणु विखंडन श्रृंखला प्रतिक्रिया की शुरुआत का यह मील का पत्थर देश को दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकी क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी सुरक्षा

मानदंडों को पूरा करने के बाद पीएफबीआर ने क्रिटिकैलिटी प्राप्त कर ली।

तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भारत का पहला स्वदेशी फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर है। 500 मेगावाट क्षमता वाले इस उन्नत रिएक्टर को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने डिजाइन और भारतीय नाभिकीय विद्युत् निगम लिमिटेड ने निर्मित किया है। इसे बनाने में 200 से अधिक भारतीय उद्योगों और लघु एवं मध्यम उद्योगों की भूमिका रही है। इस रिएक्टर को भविष्य में थोरियम-232 का उपयोग करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। जो स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए भारत के विशाल थोरियम भंडार का दोहन करने के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।



क्या होती है क्रिटिकैलिटी - यह परमाणु रिएक्टर के संचालन की वह स्थिति है जिसमें परमाणु विखंडन की श्रृंखला प्रक्रिया स्थिर हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि यह रिएक्टर अब बिना किसी बाहरी दखल के मौजूदा ईंधन के द्वारा ऊर्जा बनाने के लिए तैयार हो गया है। क्रिटिकैलिटी प्राप्त करना सीधे बिजली बनाना नहीं है अपितु यह उसके लिए पहली अनिवार्यता है। अब इस रिएक्टर की क्षमता और कुशलता को समझने के लिए कम क्षमता वाले कुछ परीक्षण किये जाएंगे जिसके बाद इसे पावर ग्रिड से जोड़कर बिजली उत्पादन शुरू किया जा सकता है।

यह उपलब्धि मात्र एक रिएक्टर चलाने

की नहीं है, इससे भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी। इससे 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कम कचरा पैदा करता है यह यूरेनियम और प्लूटोनियम का बेहतर उपयोग करता है। इससे भविष्य में बिजली सस्ती होगी। देश ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में मजबूत बनेगा। भविष्य में और अधिक ऐसे रिएक्टर बनाए जा सकेंगे जो थोरियम का इस्तेमाल कर बिजली बनाएंगे।

यह रिएक्टर 2004 में शुरू हुआ था लेकिन कई तकनीकी चुनौतियों, देरी और लागत बढ़ने के कारण अब जाकर क्रिटिकैलिटी प्राप्त कर सका है। तरल सोडियम को संभालना, सुरक्षा मानक पूरा करना और बहुत सारे परीक्षण करना असान नहीं था। इसका बजट बढ़ा किंतु सरकार का

पूरा समर्थन मिलता रहा। अब यह सफलता दिखाती है कि भारत कठिन टेक्नोलॉजी में भी आत्मनिर्भर हो सकता है। पूर्व परमाणु ऊर्जा आयोग अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर ने इस सफलता को ऐतिहासिक बताया है और कहा कि यह भारत के तीन चरण के कार्यक्रम को नई दिशा व गति देगा। यह उन्नत रिएक्टर खपत से अधिक ईंधन उत्पादन करने में सक्षम है जो देश की वैज्ञानिक क्षमता को और इंजीनियरिंग कौशल की मजबूती को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे कार्यक्रम के तीसरे चरण में भारत के विशाल थोरियम भंडार के उपयोग की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस परियोजना में शामिल वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी और इस सफलता को भारत वैज्ञानिक कौशल का प्रमाण बताया।

सरकार ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। जापान फ्रांस और अमेरिका आदि देश सुरक्षा चिंताओं के कारण ऐसी परियोजनाएं बंद कर चुके हैं परंतु भारत की स्थिति और जरूरत दोनों ही अलग है।



नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट

विनिर्माण प्रेरक शक्ति एवं आपूर्ति-श्रृंखला का अद्भुत केंद्र



डॉ. शिवेश प्रताप

संयोजक, विज्ञान विकसित भारत नीति एवं अनुसंधान

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भारत के विमानन और अवसंरचना परिदृश्य में एक ऐतिहासिक छलांग का प्रतीक है, जो इसे एशिया के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों में स्थान दिलाता है। नोएडा में रणनीतिक रूप से स्थित यह हवाई अड्डा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सशक्त करेगा, इंदिरा गांधी

इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दबाव को कम करेगा तथा औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स विकास को गति प्रदान करेगा। इसके संचालन से इस क्षेत्र को एक आधुनिक, बहु-माध्यम (मल्टीमॉडल) अर्थव्यवस्था के तहत विनिर्माण, निर्यात और एकीकृत आपूर्ति-श्रृंखलाओं के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित होने की दिशा में बढ़ावा मिलेगा।

जैसे-जैसे भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, अवसंरचना को नीति रणनीति के केंद्र में रखा गया है। पीएम गति शक्ति, पीएम मित्र पार्क, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी तथा मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों पर मोदी सरकार का विशेष जोर एक ऐसे समन्वित दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी को विनिर्माण विकास की रीढ़ माना गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में, जेवर स्थित

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक प्रमुख परियोजना के रूप में उभर रहा है, जो नीतिगत संकल्प को जमीनी क्षमता में परिवर्तित करेगा। इसे एक कार्गो-केंद्रित, बहु-माध्यमीय प्रवेश द्वार के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर स्थित है।

पहले चरण में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्रति वर्ष लगभग 1.2 करोड़ यात्रियों और लगभग 2.49 लाख टन कार्गो संभालने के लिए विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही 87 एकड़ का एक समर्पित कार्गो हब तैयार किया जा रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय कार्गो टर्मिनल को सीधे वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों से जोड़ेगा। यह स्थल दादरी में स्थित वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के

निकट है, साथ ही प्रस्तावित मल्टीमहडल लॉजिस्टिक्स एवं ट्रांसपोर्ट हब तथा कई एक्सप्रेसवे से भी जुड़ा हुआ है। एयरपोर्ट के विकास के समानांतर, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मेडिकल डिवाइसेस, खिलौने, परिधान, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर और अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी (टर्मिनल से लगभग 4 किमी दूर) जैसे क्षेत्र-विशिष्ट औद्योगिक पार्कों की अधिसूचना जारी की है। ये सभी मिलकर “मेक इन इंडिया” के तहत विनिर्माण, निर्यात और रोजगार के लिए एक एकीकृत औद्योगिक ढांचा तैयार करते हैं।

1) **मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी : लॉजिस्टिक्स बाधाओं में कमी** - जेवर एयरपोर्ट की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत इसकी कनेक्टिविटी है। दादरी जो इसके पास स्थित है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) का उत्तरी केंद्र है और खुर्जा के माध्यम से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (EDFC) से भी जुड़ता है। यह एक उच्च क्षमता वाली डबल-स्टैक रेल नेटवर्क तैयार करता है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को पश्चिम में जेएनपीटी बंदरगाह और पूर्व के प्रमुख बंदरगाहों से जोड़ता है। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल और वस्त्र जैसे समय-संवेदनशील क्षेत्रों के लिए एक मजबूत लॉजिस्टिक्स तंत्र विकसित होता है।

रेल कनेक्टिविटी के अलावा, नेशनल इंडस्ट्रियल अथॉरिटी कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दादरी में 849 एकड़ का मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब और 360 एकड़ का मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब विकसित कर रहा है, जिसमें ₹4,034 करोड़ से अधिक का निवेश किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से लगभग ₹1.15 लाख करोड़ की आर्थिक क्षमता उत्पन्न होने और लगभग 1 लाख रोजगार सृजित होने का अनुमान है। WDFC और EDFC के संगम पर तथा इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप के पास स्थित होने के कारण, ये हब आयात और निर्यात

दोनों के लिए निर्बाध मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे।

सड़क कनेक्टिविटी भी उतनी ही मजबूत है। यह एयरपोर्ट सीधे यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है और जेवर-फरीदाबाद लिंक के माध्यम से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से भी जुड़ेगा। साथ ही, यह कुंडली- गाजियाबाद-पलवल (KGP) एक्सप्रेसवे और अन्य क्षेत्रीय कॉरिडोर से भी कनेक्ट होगा। भविष्य में मेट्रो और रैपिड रेल कनेक्टिविटी की भी योजना बनाई गई है, जिससे यह एयरपोर्ट एनसीआर के आर्थिक भूगोल के साथ और अधिक एकीकृत हो सकेगा।

निकट अवधि में, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने बस सेवाओं और राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी कर पहले और अंतिम मील कनेक्टिविटी की व्यवस्था शुरू कर दी है, जिससे बड़े ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स के शुरू होने तक पहुंच संबंधी चुनौतियों को कम किया जा सके। निर्माताओं के लिए यह मल्टीमॉडल नेटवर्क गति, पूर्वानुमान और आपूर्ति-श्रृंखला में फंसी कार्यशील पूंजी को कम करने में सहायक होगा। उच्च मूल्य के निर्यात के लिए एयर कार्गो, भारी माल और कंटेनर परिवहन के लिए DFC रेल नेटवर्क तथा क्षेत्रीय परिवहन के लिए एक्सप्रेसवे इन सभी के संयोजन से जेवर एयरपोर्ट एक व्यापक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का केंद्रीय स्तंभ बनकर उभरता है।

जेवर एयरपोर्ट के आसपास विकसित यह मल्टीमॉडल एकीकरण केवल एक अवसर-रचनात्मक उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की लॉजिस्टिक्स प्रणाली की संरचनात्मक समस्याओं का एक नीतिगत समाधान भी है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे और मल्टीमॉडल हब से जुड़कर यह परियोजना सरकार के उस लक्ष्य को साकार करती है, जिसके तहत लॉजिस्टिक्स लागत को जीडीपी के 10 प्रतिशत से नीचे लाना है। इससे निर्यातकों को सीधे लाभ मिलेगा। डिलीवरी समय कम होगा, विश्वसनीयता बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस तथा

टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर विस्तार का अवसर मिलेगा।

और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह परियोजना भारतमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोग्राम और पीएम गति शक्ति जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो मिलकर एक एकीकृत लॉजिस्टिक्स ग्रिड तैयार कर रहे हैं। यही समेकित ढांचा भारत की औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करेगा और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को गति देगा।

2) **सेक्टर-विशिष्ट पार्क : कनेक्टिविटी को औद्योगिक क्लस्टर में बदलना** - यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जेवर को केवल एक हवाई अड्डा परियोजना के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यापक औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के केंद्र (न्यूक्लियस) के रूप में परिकल्पित किया है। एयरपोर्ट के आसपास भूमि को सेक्टर-विशिष्ट पार्कों के लिए चिन्हित और आवंटित किया जा रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय कार्गो गेटवे और दादरी स्थित DFC-आधारित लॉजिस्टिक्स क्षमता का सीधा लाभ उठाते हैं। इस क्लस्टर-आधारित मॉडल से उद्योगों को फैंक्ट्री गेट पर ही निर्यात-स्तरीय लॉजिस्टिक्स उपलब्ध होती है, जिससे लागत और समय दोनों में उल्लेखनीय कमी आती है।

सबसे प्रमुख परियोजनाओं में सेक्टर-28 का लगभग 350 एकड़ में फैला मेडिकल डिवाइसेस पार्क है, जिसमें गामा रेडिएशन स्ट्रलाइजेशन जैसी उन्नत सुविधाएं शामिल हैं। यह देश में डिस्पोजेबल, इम्प्लांट्स, डायग्नोस्टिक्स और चिकित्सा उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देगा। इसके निकट ही सेक्टर-10 में सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है, जिसे 2025 में HCL-Foxconn परियोजना की मंजूरी से नई गति मिली। यह संयंत्र प्रति माह 3.6 करोड़ डिस्ले ड्राइवर ICs का उत्पादन करेगा और लगभग 2,000 प्रत्यक्ष रोजगार

सृजित करेगा, साथ ही एक व्यापक इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन को विकसित करेगा।

श्रम-प्रधान उद्योगों को समर्थन देने के लिए सेक्टर-33 में टॉय पार्क विकसित किया गया है, जहां 130-140 प्लॉट आवंटित किए जा चुके हैं और 100 से अधिक इकाइयों को कब्जा दिया जा चुका है। उत्पादन शुरू होने पर यह पार्क हजारों रोजगार सृजित करेगा। इसके समानांतर, सेक्टर-29 में अपैरल, MSME और हस्तशिल्प पार्क विकसित किए जा रहे हैं, जो फैशन निर्यात के लिए एयर कार्गो और घरेलू वितरण के लिए DFC रेल नेटवर्क का उपयोग करेंगे।

डिजिटल अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सेक्टर-28 में डेटा सेंटर पार्क विकसित किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व Yotta Infrastructure कर रही है। यहां 30,000 रैक और 160-250 मेगावाट IT पावर क्षमता वाला हाइपरस्केल डेटा सेंटर प्रस्तावित है, जो AI, क्लाउड और डिजाइन आधारित उद्योगों को शक्ति प्रदान करेगा। वहीं सेक्टर-21 में लगभग 1,000 एकड़ में अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी विकसित की जा रही है, जो एयरपोर्ट से मात्र 4 किमी दूरी पर होगी और AVGC (Animation, VFX, Gaming, Comics) जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देगी।

ये सभी सेक्टर पार्क मिलकर मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम के लक्ष्यों को साकार करते हैं। ये भारत के विनिर्माण क्षेत्र की पुरानी चुनौतियों की कमी, कमजोर सप्लाई चेन लिंक और वैश्विक बाजार तक सीमित पहुंच को दूर करते हैं और बड़े पैमाने पर प्रतिस्पर्धी उत्पादन को संभव बनाते हैं।

3) तैयार इलेक्ट्रॉनिक्स आधार : मेक इन इंडिया को नई गति : नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसे क्षेत्र में विकसित हो रहा है, जो पहले से ही भारत के सबसे मजबूत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्रों में से एक है। उत्तर प्रदेश देश के लगभग 55 प्रतिशत मोबाइल उत्पादन और करीब 15

प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में योगदान देता है।

इस पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करते हुए, सैमसंग का ग्रेटर नोएडा प्लांट अब लैपटॉप उत्पादन भी कर रहा है, जिससे भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में विविधता आ रही है। जैसे ही जेवर एयरपोर्ट पूर्ण रूप से चालू होगा और दादरी के DFC नेटवर्क से जुड़ेगा, निर्यात-उन्मुख इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी। इससे ऑर्डर से डिलीवरी तक

पहले चरण में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्रति वर्ष लगभग 1.2 करोड़ यात्रियों और लगभग 2.49 लाख टन कार्गो संभालने के लिए विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही 87 एकड़ का एक समर्पित कार्गो हब तैयार किया जा रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय कार्गो टर्मिनल को सीधे वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों से जोड़ेगा।

का समय काफी कम होगा और भारत उच्च मूल्य श्रृंखला में ऊपर बढ़ सकेगा।

4) सप्लाई-चेन "मार्शल" : कैसे जुड़ते हैं सभी घटक- जेवर पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे बड़ी ताकत इसकी समेकित संरचना है, जहां सभी घटक एक निर्बाध सप्लाई चेन में जुड़ते हैं। एयरपोर्ट का कार्गो हब वेयरहाउसिंग से सीधे जुड़ा है, जिससे परिवहन में समय की बचत होती है और उत्पाद तेजी से बाजार तक पहुंचते हैं। दादरी

स्थित मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ मिलकर यह प्रणाली उद्योगों को सबसे उपयुक्त माध्यम हवाई या रेल का चयन करने की सुविधा देती है।

क्लस्टर-आधारित विकास उत्पादकता को भी बढ़ाता है। सेक्टर-विशिष्ट पार्कों में परीक्षण केंद्र, डिजाइन लैब, टूल रूम और लॉजिस्टिक्स सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं, जिससे "जस्ट-इन-टाइम" उत्पादन और नए उत्पादों की तेजी से लॉन्चिंग संभव होती है। मेडिकल डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर, खिलौने, वस्त्र और डेटा सेंटर ये सभी एक-दूसरे को सपोर्ट करते हुए एक एकीकृत वैल्यू चेन बनाते हैं।

यह पूरा ढांचा मेक इन इंडिया, इंडिया सेमिकंडक्टर मिशन और उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीतियों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। निवेश के संकेत पहले ही स्पष्ट हैं, जैसे HCL-Foxconn परियोजना और YEIDA द्वारा लगातार प्लॉट आवंटन।

रोजगार के दृष्टिकोण से भी यह परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। दादरी मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब से ही लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होने की संभावना है, जबकि सेमीकंडक्टर इकाई लगभग 2,000 और टॉय पार्क हजारों नौकरियां सृजित करेगा।

अंततः, जेवर केवल एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि एक संपूर्ण लॉजिस्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो फ्रेट कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे और औद्योगिक पार्कों के साथ एकीकृत है। यह वही मॉडल है जो "मेक इन इंडिया" को वास्तविक निर्यात, निवेश और रोजगार में परिवर्तित करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जेवर भारत को केवल असेंबली बेस से आगे बढ़ाकर एक सशक्त वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की क्षमता रखता है, जहां प्रतिस्पर्धात्मकता केवल लक्ष्य नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की संरचना में निहित है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम शिक्षा से आगे, अब सत्ता तक



ऋचा सिंह
शासकीय शिक्षिका, कुशीनगर



राष्ट्र-चिंतन केवल सीमाओं, अर्थव्यवस्था और विकास-दरों का प्रश्न नहीं है; यह इस बात का भी प्रश्न है कि देश की नीतियां किन अनुभवों, किन आवाजों और किन जीवन-यथार्थों से बन रही हैं। जब किसी लोकतंत्र में आधी आबादी की भागीदारी निर्णय-निर्माण की केंद्रीय संस्थाओं में सीमित रह जाती है, तब विकास का ढांचा भी अधूरा रह जाता है। भारत में महिलाएं लंबे समय से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, श्रम, परिवार, समुदाय और सामाजिक संरक्षण के क्षेत्र में वास्तविक जिम्मेदारियां निभाती रही हैं, पर राजनीतिक सत्ता-संरचना में उनका प्रतिनिधित्व उसी अनुपात में नहीं बढ़ सका। इसी ऐतिहासिक असंतुलन को दूर करने की दिशा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक महत्वपूर्ण संवैधानिक कदम है।

यह अधिनियम केवल सीटों का आरक्षण नहीं है; यह भारतीय लोकतंत्र को अधिक प्रतिनिधिक, अधिक न्यायपूर्ण और अधिक व्यावहारिक बनाने की दिशा में एक

संरचनात्मक हस्तक्षेप है। लंबे समय तक महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को प्रतीकात्मक समर्थन मिला, पर संस्थागत अवसर नहीं मिले। परिणाम यह हुआ कि महिलाएं मतदान में सक्रिय होने, प्रशासन, शिक्षा, सेना, विज्ञान, उद्यमिता और स्थानीय नेतृत्व में अपनी क्षमता सिद्ध करने के बावजूद संसद और विधानसभाओं में पर्याप्त संख्या तक नहीं पहुंच पाईं। इसलिए यह प्रश्न अब केवल “महिलाओं को अवसर देने” का नहीं, बल्कि लोकतंत्र को उसके वास्तविक अर्थ तक पहुंचाने का है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : बराबरी का वादा, पर प्रतिनिधित्व का अभाव - भारत ने स्वतंत्रता के साथ ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाया। संविधान ने अनुच्छेद 14, 15 और 16 के माध्यम से समानता, भेदभाव-निषेध और अवसर की समानता का वादा किया। अनुच्छेद 15(3) ने राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति भी दी।

इसके बावजूद, लोकतंत्र की सर्वोच्च निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं की उपस्थिति बहुत धीमी गति से बढ़ी।

पहली लोकसभा (1952) में कुल 489 सदस्यों में केवल 22 महिलाएं निर्वाचित हुई थीं, यानी लगभग 4.5 प्रतिशत। कई दशकों बाद 17वीं लोकसभा (2019) में 78 महिलाएं चुनी गईं, जो कुल 543 सदस्यों का लगभग 14.4 प्रतिशत है। यह प्रगति महत्वपूर्ण अवश्य है, पर यह भी स्पष्ट करती है कि सात दशकों से अधिक समय में भी संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी उनके जनसंख्या अनुपात के आसपास नहीं पहुंच सकी। यही स्थिति अधिकांश राज्य विधानसभाओं में भी दिखाई देती है, जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व लंबे समय तक औसतन लगभग 10 प्रतिशत के आसपास ही रहा।

यह स्थिति इसलिए और भी गंभीर लगती है क्योंकि स्थानीय निकायों में आरक्षण ने बिल्कुल अलग तस्वीर प्रस्तुत की। 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के बाद

पंचायतों और नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था हुई, जिससे लाखों महिलाओं को पहली बार औपचारिक राजनीतिक नेतृत्व का अवसर मिला। विभिन्न सरकारी आंकड़ों के अनुसार पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या 14 लाख से अधिक रही है। इस अनुभव ने यह साबित किया कि अवसर मिलने पर महिलाएं केवल निर्वाचित ही नहीं होतीं, बल्कि शासन की प्राथमिकताओं को भी बदलती हैं।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है : सितंबर 2023 में संसद ने महिलाओं के लिए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान करने वाला संविधान संशोधन पारित किया, जिसे सामान्यतः नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है। यह अधिनियम संविधान का 106वाँ संशोधन है। इसके तहत महिलाओं के लिए सामान्य सीटों के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वर्गों के भीतर भी एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

हालांकि, इसका क्रियान्वयन तत्काल प्रभाव से चुनावों में स्वतः लागू नहीं हो जाता; अधिनियम के अनुसार यह व्यवस्था अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन की प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। इसलिए इस कानून का राजनीतिक महत्व दो स्तरों पर समझना चाहिए- पहला, यह महिलाओं की विधायी भागीदारी को संवैधानिक मान्यता देता है; दूसरा, यह भविष्य के प्रतिनिधित्व ढाँचे को बदलने की दिशा तय करता है।

केवल शिक्षा नहीं, सत्ता में भागीदारी क्यों आवश्यक है : अक्सर यह माना जाता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसरों तक सीमित है। निस्संदेह, शिक्षा सशक्तिकरण का आधार है; पर केवल पढ़-लिख लेने से शक्ति-संतुलन नहीं बदलता, जब तक निर्णय लेने वाली संस्थाओं में बराबर भागीदारी न हो। नीति-निर्माण वह स्थल है जहां यह तय

होता है कि सार्वजनिक धन कहां खर्च होगा, किस मुद्दे को प्राथमिकता मिलेगी, किन अधिकारों को कानूनी संरक्षण मिलेगा, और कौन-सी समस्याएं “निजी” कहकर टाल दी जाएंगी।

पानी, स्वच्छता, पोषण, मातृ स्वास्थ्य, विद्यालयी अवसंरचना, क्रेच, सार्वजनिक परिवहन, कार्यस्थल सुरक्षा, लैंगिक हिंसा, वेतन असमानता, देखभाल-आधारित श्रम, घरेलू काम का बोझ, ये सभी मुद्दे महिलाओं के जीवन से सीधे जुड़े हुए हैं। जब निर्णय-निर्माण के मंचों पर महिलाओं की

यह अधिनियम केवल सीटों का आरक्षण नहीं है; यह भारतीय लोकतंत्र को अधिक प्रतिनिधिक, अधिक न्यायपूर्ण और अधिक व्यावहारिक बनाने की दिशा में एक संरचनात्मक हस्तक्षेप है। लंबे समय तक महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को प्रतीकात्मक समर्थन मिला, पर संस्थागत अवसर नहीं मिले। परिणाम यह हुआ कि महिलाएं मतदान में सक्रिय होने, प्रशासन, शिक्षा, सेना, विज्ञान, उद्यमिता और स्थानीय नेतृत्व में अपनी क्षमता सिद्ध करने के बावजूद संसद और विधानसभाओं में पर्याप्त संख्या तक नहीं पहुंच पाईं।

उपस्थिति कम होती है, तब इन मुद्दों का स्थान भी अक्सर नीतिगत प्राथमिकताओं में नीचे चला जाता है। इसलिए सत्ता में भागीदारी कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक न्याय का आवश्यक तत्व है।

शिक्षा की प्रगति और उसकी सीमाएं : भारत में महिलाओं की शिक्षा में

उल्लेखनीय सुधार हुआ है, पर यह सुधार भी बहुत लंबी और कठिन यात्रा का परिणाम है। 1951 की जनगणना में महिला साक्षरता दर लगभग 8.9 प्रतिशत थी। 2011 की जनगणना तक यह बढ़कर लगभग 65.5 प्रतिशत हो गई। यह परिवर्तन निश्चय ही ऐतिहासिक है, पर इसके भीतर क्षेत्रीय असमानताएं, ग्रामीण-शहरी विभाजन, जातीय और वर्गीय अंतर अब भी मौजूद हैं।

उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और हाल के वर्षों में कुल नामांकन अनुपात में महिलाओं की हिस्सेदारी कई क्षेत्रों में बेहतर हुई है। अधिक सावधान और तथ्यसंगत बात यह है कि उच्च शिक्षा में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ी है।

आर्थिक भागीदारी : अवसर और अवरोध - राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी को महिलाओं की आर्थिक स्थिति से अलग करके नहीं देखा जा सकता। पीरियहडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) 2022-23 के अनुसार भारत में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर में पिछले वर्षों की तुलना में सुधार हुआ है, पर पुरुषों की तुलना में अंतर अभी भी बड़ा है। प्रचलित सरकारी आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की श्रम भागीदारी लगभग 37 प्रतिशत और पुरुषों की लगभग 78 प्रतिशत के आसपास रही।

भारत की महिलाएं बड़ी मात्रा में घरेलू और देखभाल-आधारित अवैतनिक कार्य करती हैं। टाइम यूज सर्वे ने यह स्पष्ट किया है कि महिलाओं द्वारा घरेलू सेवाओं और परिवार-देखभाल में लगाया जाने वाला समय पुरुषों की तुलना में कई गुना अधिक है। इसलिए किसी महिला की आर्थिक भागीदारी का आकलन केवल वेतनभोगी कार्य से नहीं किया जा सकता। समाज जिस श्रम पर रोज चलता है, उसका एक बड़ा हिस्सा महिलाओं के अदृश्य, अवैतनिक और कम-मूल्यांकित काम पर टिका है।

कृषि में भी महिलाओं की भूमिका केंद्रीय है, पर भूमि और संपत्ति पर उनका अधिकार सीमित है। कृषि जनगणना और

संबंधित अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि महिलाओं के नाम पर परिचालन जोतों का अनुपात पुरुषों की तुलना में काफी कम है। इसलिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सवाल यहां फिर लौट आता है। यदि भूमि, श्रम, आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और देखभाल-अर्थव्यवस्था से जुड़े निर्णय लेने वाली संस्थाओं में महिलाएँ पर्याप्त संख्या में होंगी, तभी इन मुद्दों को संरचनात्मक प्राथमिकता मिल सकेगी।

पंचायत से संसद तक : अनुभव क्या कहता है : महिलाओं के लिए राजनीतिक आरक्षण का सबसे मजबूत तर्क भारत का अपना स्थानीय अनुभव है। पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण ने यह मिथक तोड़ा कि महिलाएं चुनाव जीत नहीं सकतीं, प्रशासन नहीं समझ सकतीं, या नेतृत्व की क्षमता नहीं रखतीं। अनेक अध्ययनों ने दिखाया है कि महिला नेतृत्व स्थानीय शासन में पेयजल, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, सड़क, स्वच्छता और समुदाय-आधारित समस्याओं के समाधान को अधिक प्रमुखता दे सकता है।

यह भी सच है कि स्थानीय स्तर पर कई जगह 'सरपंच पति' या प्रॉक्सी नेतृत्व जैसी चुनौतियां सामने आईं। पर यह चुनौती आरक्षण की विफलता नहीं, बल्कि पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना की प्रतिक्रिया है। समय के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने इन सीमाओं को तोड़ा और स्वतंत्र नेतृत्व स्थापित किया। इसी अनुभव ने यह आधार दिया कि यदि स्थानीय निकायों में महिलाएं प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं, तो संसद और विधानसभाओं में भी उनका प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए।

यह अधिनियम क्यों आवश्यक था : महिला आरक्षण के पक्ष में केवल नैतिक तर्क ही नहीं, व्यावहारिक तर्क भी अत्यंत मजबूत हैं। पहला, स्वैच्छिक राजनीतिक सुधार पर्याप्त नहीं रहे। राजनीतिक दल लंबे समय तक महिला सशक्तिकरण की बात करते रहे, लेकिन टिकट वितरण में महिलाओं को

सीमित अवसर दिए गए। यदि दल स्वेच्छा से संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर पाते, तो संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या अब तक कहीं अधिक होती।

दूसरा, प्रतिनिधित्व स्वयं नीति को प्रभावित करता है। यह मानना सरल होगा कि कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि हर मुद्दे पर समान रूप से संवेदनशील होगा; पर व्यवहार में अनुभव, सामाजिक स्थिति और जीवन-यथार्थ नीतिगत प्राथमिकताओं को प्रभावित करते हैं। महिलाओं की पर्याप्त उपस्थिति से कानून निर्माण, संसदीय बहस, समितियों की सक्रियता और बजटीय प्राथमिकताओं में परिवर्तन की संभावना बढ़ती है।

तीसरा, लोकतंत्र में वैधता का प्रश्न। यदि देश की लगभग आधी आबादी निर्णय लेने वाली संस्थाओं में लगातार कम प्रतिनिधित्व में रहे, तो लोकतंत्र औपचारिक रूप से तो पूर्ण दिख सकता है, पर प्रतिनिधिक दृष्टि से अधूरा रहेगा। लोकतंत्र केवल मतदान का अधिकार नहीं, बल्कि सत्ता-संरचना में न्यायपूर्ण सहभागिता भी है।

संभावित प्रभाव : केवल संख्या नहीं, शासन की दिशा में बदलाव : इस अधिनियम का महत्व केवल इस बात में नहीं है कि अधिक महिलाएं सदनों में पहुंचेंगी; असली महत्व इस संभावना में है कि शासन की भाषा और प्राथमिकताएं बदलेगीं। जब अधिक संख्या में महिला विधायक और सांसद होंगी, तो संसद और विधानसभाओं की बहस में रोजमर्रा के वे प्रश्न अधिक स्पष्ट होकर आएंगे जिन्हें अक्सर निजी या गौण मान लिया जाता है।

सावधानी की जरूरतरु केवल आरक्षण से सब कुछ नहीं बदलेगा : इस अधिनियम का स्वागत करते हुए कुछ जरूरी सावधानियां भी समझनी होंगी। पहली, इसका क्रियान्वयन जनगणना और परिसीमन से जुड़ा है, इसलिए इसके वास्तविक प्रभाव के लिए प्रशासनिक और संवैधानिक प्रक्रियाओं का पूरा होना आवश्यक है। दूसरी, महिलाओं

का प्रतिनिधित्व केवल संख्या तक सीमित न रह जाए; विविध सामाजिक पृष्ठभूमियों, ग्रामीण, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, श्रमिक, पेशेवर, युवा महिलाओं को भी नेतृत्व अवसर मिलें। तीसरी, दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र और महिला नेतृत्व-निर्माण के बिना आरक्षण का लाभ सीमित हो सकता है।

शिक्षा से सत्ता तक खुलता हुआ रास्ता : भारत में महिलाओं की यात्रा शिक्षा, श्रम, सामाजिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी के अनेक पड़ावों से होकर गुजरी है। शिक्षा ने चेतना जगाई, रोजगार ने आत्मनिर्भरता की आकांक्षा दी, स्थानीय निकायों ने नेतृत्व का प्रशिक्षण दिया, और अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम राष्ट्रीय तथा प्रांतीय स्तर की सत्ता-संरचना में साझेदारी का संवैधानिक आधार देता है।

इसलिए यह कानून दया का परिणाम नहीं, बल्कि देर से मिले लोकतांत्रिक न्याय का परिणाम है। यह महिला को केवल लाभार्थी या प्रतीक भर नहीं रहने देता, बल्कि उसे विधायी और नीतिगत निर्णयों की सक्रिय भागीदार के रूप में स्थापित करने का मार्ग खोलता है। जब लोकतंत्र की संस्थाओं में महिलाओं की उपस्थिति उनकी जनसंख्या, उनके श्रम, उनके अनुभव और उनके योगदान के अधिक निकट पहुंचेगी, तभी "हम भारत के लोग" का भाव अधिक पूर्ण अर्थ ग्रहण करेगा।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम का सबसे बड़ा संदेश यही है कि राष्ट्र का भविष्य तब अधिक संतुलित, अधिक मानवीय और अधिक दूरदर्शी बनता है, जब शिक्षा से सशक्त हुई महिला सत्ता में भी सहभागी बनती है। शिक्षा विचार बदलती है, पर सत्ता व्यवस्था बदलती है। और जब विचार और व्यवस्था दोनों में महिला की समान हिस्सेदारी सुनिश्चित होती है, तभी वास्तविक लोकतांत्रिक समानता का मार्ग प्रशस्त होता है।

कॉर्पोरेट जिहाद

जिहादियों के लिए संविधान, हिंदुओं और इंसानियत को नुकसान पहुंचाने का एक और तरीका



डॉ. पंकज जगन्नाथ जयस्वाल
वरिष्ठ पत्रकार एवं शिक्षाविद

म हाराष्ट्र के नासिक में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में हाल ही में हुआ भयानक 'कॉर्पोरेट जिहाद' बहुत परेशान करने वाला है और यह सभी भारतीयों, खासकर हिंदुओं (जैन, बौद्ध, सिख, वगैरह सहित) के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए। नासिक पुलिस की शानदार टीम को इस इंसानियत-विरोधी 'कॉर्पोरेट जिहाद' की जांच करने और उसे बेनकाब करने की उनकी लगातार कोशिशों के लिए सन्मान मिलना चाहिए। लेफ्ट इस्लामिक दुनिया और भारत में कई कट्टरपंथी मुसलमानों का ग्लोबल प्लान हिंदुओं को सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक तौर से नीचा दिखाना है ताकि गैर-कानूनी तरीके से इस्लाम में धर्म बदलना आसान हो जाए, साथ ही सरकारी और प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा करके हिंदुओं को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया जा सके।

जिहाद के अलग-अलग रूप, जैसे लव जिहाद, लैंड जिहाद, इकोनॉमिक जिहाद, फूड जिहाद, और अब कॉर्पोरेट जिहाद, और कोई नहीं जानता कि कितने अलग-अलग तरह के जिहाद हो रहे हैं या भविष्य में कितने नए जिहाद शुरू हो सकते हैं। जो लोग अब भी मानते हैं कि समाज में ऐसा कुछ नहीं हो रहा



है, उन्हें किसी ऐसी लड़की या औरत से मिलना चाहिए जो लव जिहाद का शिकार हुई हो। उस किसान या जमीन के मालिक से मिलें जिसने वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत अपनी ज़मीन खो दी; अगर आपको कुछ भी गलत नहीं लगता, तो आप इंसान नहीं, राक्षस हैं। ये सभी जिहाद गैर-संवैधानिक हैं और सुप्रीम कोर्ट और अलग-अलग सरकारों को इन्हें संवैधानिक तरीके से सुलझाना चाहिए।

कॉर्पोरेट जिहाद, हिंदू महिलाओं को टारगेट करने का एक नया तरीका : नासिक की घटना ने कॉर्पोरेट दुनिया को हिलाकर रख दिया है, जिससे हिंदुओं, खासकर हिंदू महिला कर्मचारियों के खिलाफ एक गहरी साजिश का पता चला है। उन्हें परेशान किया गया, मारपीट की गई, रेप किया गया, गाय का बीफ खाने के लिए मजबूर किया गया, और एक रणनीतिक तरीके से इस्लामी धार्मिक परंपराओं का

पालन करने के लिए मजबूर किया गया। क्या यह कॉर्पोरेट ऑफिस में चल रही सबसे बुरी तरह की इंसानियत विरोधी गतिविधि नहीं है? इस्लामी धार्मिक समूह और एक अलग WhatsApp ग्रुप के जरिए सावधानी से की गई तैयारी हिंदू धर्म को कमजोर करने में लेफ्ट इस्लामिक दुनिया के गहरे और बाहरी समर्थन को भी दिखाती है। सेंट्रल एजेंसियों को इस गहरी साजिश को समझने और यह समझने के लिए सभी नजरिए से जांच करनी चाहिए कि यह दूसरी संस्थाओं तक कैसे फैली है।

सरकार और अलग-अलग इकाईया अब आराम से बैठकर अगले कॉर्पोरेट हमले का इंतजार नहीं कर सकते। नासिक पुलिस टीम, खासकर महिला पुलिस कर्मियों ने बहुत अच्छी काबिलियत दिखाई और सच सामने लाने और सबूत इकट्ठा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। यह खतरा जनता को

पता ही नहीं चल पाता। हम हर जगह एक जैसी कार्रवाई की उम्मीद नहीं कर सकते, इसलिए ध्यान रखने वाले माता-पिता, कर्मचारी, सहकर्मी, मैनेजमेंट, समाज, पुलिस और सरकार को नजर रखनी चाहिए, और अगर कुछ भी संदिग्ध मिले, तो सही कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जो कोई भी कॉर्पोरेट दुनिया में, या किसी भी संगठन या संस्थान में इस तरह के गंदे खेल के बारे में जानता है, और चुप रहता है, वह इंसानियत के खिलाफ काम करने वाला एक शैतान है।

अच्छे मुसलमानों के काम बहुत जरूरी हैं।

हिंदू एकता बहुत जरूरी है; नहीं तो, ब्रेनवॉश किए हुए जिहादी हिंदुओं और इस शानदार देश को नुकसान पहुंचाने के लिए कई तरह से काम करते रहेंगे। अच्छे मुसलमानों को कट्टर मुसलमानों, संस्थाओं और संगठनों का कड़ा विरोध करना चाहिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की पहल करनी चाहिए जो दूसरे धर्मों के साथ-साथ इंसानियत के खिलाफ काम करते हैं। अच्छे मुसलमानों को सरकार और पुलिस को बताना चाहिए कि जो भी मदरसे बच्चों में जहरीली सोच या शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें कानून के मुताबिक बंद कर दिया जाए या रेगुलर स्कूल में बदल दिया जाए। अच्छे मुसलमानों ने मस्जिदों और मौलवियों पर भी नजर रखनी चाहिए कि वे क्या सिखाते हैं और नमाज पढ़ने आने वाले लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। अगर कोई गैर-कानूनी गतिविधि या नफरत फैलाने वाली बातें देखी जाती हैं, तो पुलिस अधिकारियों को तुरंत बताया जाना चाहिए। अच्छे मुसलमानों को मस्जिदों, मदरसों, या किसी भी दूसरे संगठन या संस्थान को मिलने वाले फंड पर नजर रखनी चाहिए जो किसी सामाजिक मकसद के लिए काम करते हैं, खासकर मुसलमानों के लिए; अगर पैसा गलत सोर्स से गलत मकसद के लिए आ रहा है, तो इसकी तुरंत सही जानकारी सरकारी अधिकारियों को रिपोर्ट करनी चाहिए। सरकार और दूसरे चौकस डिपार्टमेंट 140 करोड़ लोगों, साथ ही लाखों

संगठनों और संस्थानों की हर हरकत पर नजर नहीं रख सकते। हर इंसान की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह समाज और देश के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को संवैधानिक ढांचे के हिसाब से निभाए; तभी हमारा समाज और देश बेहतर और ज्यादा शांतिपूर्ण होगा, और हम जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ेंगे।

अब समय आ गया है कि अच्छे मुसलमान आगे आएँ और दूसरे धार्मिक ग्रुप, सरकार और न्याय व्यवस्था के बीच भरोसा बनाने के लिए अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को

जिहाद के अलग-अलग रूप, जैसे लव जिहाद, लैंड जिहाद, इकोनॉमिक जिहाद, फूड जिहाद, और अब कॉर्पोरेट जिहाद, और कोई नहीं जानता कि कितने अलग-अलग तरह के जिहाद हो रहे हैं या भविष्य में कितने नए जिहाद शुरू हो सकते हैं। जो लोग अब भी मानते हैं कि समाज में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, उन्हें किसी ऐसी लड़की या औरत से मिलना चाहिए जो लव जिहाद का शिकार हुई हो। उस किसान या जमीन के मालिक से मिलें जिसने वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत अपनी जमीन खो दी; अगर आपको कुछ भी गलत नहीं लगता, तो आप इंसान नहीं, राक्षस हैं।

काम में दिखाएं। अलग-अलग आतंकवादी संगठनों और लोगों के इंसानियत के खिलाफ कामों की वजह से न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में भरोसे की बहुत कमी है। आइए, हम भारतीय नागरिक के तौर पर आगे बढ़ें, और हमारे खूबसूरत संविधान में बताए गए देश के नियमों का पालन करें। संविधान को धार्मिक सिद्धांतों या धार्मिक कट्टरपंथियों की उम्मीदों से ऊपर रखा जाना चाहिए। देश को सबसे पहले रखने की सोच

को भारत के सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में शिक्षा के जरिए बढ़ावा देना चाहिए, और तभी हम समाज में 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' की ओर बढ़ते हुए अच्छा बदलाव देखेंगे।

अलग-अलग जिहाद से कैसे निपटा जाना चाहिए : बढ़ते लव जिहाद और लैंड जिहाद के मामलों पर समाज और सरकार को मिलकर तुरंत कानूनी और सामाजिक कार्रवाई करनी चाहिए; नहीं तो, कई हिंदू महिलाएं अपने संवैधानिक अधिकार खो रही हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है, धर्म बदल दिया जा रहा है, कुछ समय बाद फेंक दिया जा रहा है, या मार दिया जा रहा है, जो कि सबसे बुरी इंसानियत विरोधी गतिविधियों में से एक है जो हम देख रहे हैं, लेकिन हम इस खतरे को खत्म करने के लिए कानूनी तौर पर और तेजी से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सभी कर्मचारियों के इंसानियत के गुणों की रक्षा करने और उनके धर्म को खतरे में डाले बिना कंपनी की स्ट्रेटेजी को फिर से शुरू करने की जरूरत है। लोकल पुलिस और समाज को सरकारी या प्राइवेट प्रॉपर्टी पर किसी भी बिना इजाजत धार्मिक ढांचे को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ऐसे अपराधों के लिए गंभीर कानूनी कार्रवाई की जरूरत है ताकि कोई भी कानून तोड़ने की हिम्मत न करे।

मकसद किसी धर्म को टारगेट करना नहीं है, बल्कि इंसानियत और संविधान की रक्षा करना है। इन जिहादियों द्वारा हमारे संविधान को दी जा रही लगातार चुनौती पूरी इंसानियत के लिए बहुत चिंता की बात है। हम इनकार नहीं कर सकते या यह नहीं मान सकते कि ये किसी और की समस्याएँ हैं। इस सोच का समाज और देश पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इंसानियत के खिलाफ हर मुद्दा सबके लिए एक समस्या है, सिर्फ सरकार या पीड़ितों के लिए नहीं। आइए हम इंसानियत और संविधान के मकसद के लिए जागें और अपने समाज और देश को बेहतर और मजबूत बनाएं।

श्रीनगर में 36 वर्ष बाद खुला रघुनाथ मंदिर



डॉ. विनीत उत्पल
मीडिया अकादमिक, जम्मू



श्री नगर के हब्बा कदल-फतेह कदल (डाउन टाउन श्रीनगर) स्थित रघुनाथ मंदिर के कपाट मार्च, 2026 में रामनवमी के अवसर पर आम लोगों के लिए खुल गए। कश्मीरी हिन्दू परिवार ने परिसर में काफ़ी धूमधाम से पूजा-अर्चना की। मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रों का उच्चारण हुआ, हवन किये गए और भजन-कीर्तन भी हुए। शहर में इस्कोन की सहायता से राम दरबार की झांकी निकाली गई, शोभा यात्रा निकली और वह शहर के क्लॉक टावर से होकर भी गुजरी। हालाँकि अभी मंदिर में भगवान राम की मूर्ति स्थापित नहीं हुई है। बावजूद इसके फूलों और रंग-बिरंगी रोशनी से पूरे मंदिर को सजाया गया।

वर्ष 1989 से 1992 के बीच इस मंदिर पर कई आतंकी हमले हुए। उसी दौरान मंदिर के आसपास रहने वाले कश्मीरी पंडितों ने अपनी पुस्तैनी घरों को औने-पौने दाम में स्थानीय लोगों के हाथों बेच दिया और यह मंदिर कूड़ा घर में तब्दील हो गया। आतंकियों ने इस मंदिर को तबाह कर दिया था, आग लगा दी थी और मूर्तियों को तोड़कर विस्ता

यानी झेहलम (झेलम) नदी में बहा दिया था। स्थानीय लोग कहते हैं कि आतंकियों ने हिन्दुओं को मंदिर में पूजा करने से मना किया था लेकिन जब भक्तों ने आना बंद नहीं किया तो पूरे मंदिर में आग लगा दी और उसे तोड़ दिया गया और लूटपाट की। स्थानीय लोग कहते हैं कि आतंकी निजाम-ए-मुस्तफा का नारा देते हुए मंदिर में घुसे थे। मंदिर से लूटी गई 23 कीमती मूर्तियों, चांदी, सोने के आभूषणों तथा लाखों रुपये के अन्य बहुमूल्य सामान का पता पुलिस भी नहीं लगा पाई।

घाटी के रघुनाथ मंदिर का निर्माण कार्य वर्ष 1835 में महाराज गुलाब सिंह ने शुरू की थी, उनके निधन के बाद यह काम उनके पुत्र और जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराज रणबीर सिंह ने की और यह 1860 में बनकर तैयार हुआ। यह मंदिर झेलम नदी के बाएं तरफ है और यह मंदिर पहाड़ की चोटी यानी शिखर की शैली में बना हुआ है। इसमें जम्मू के रघुनाथ मंदिर परिसर की वास्तुकला शैली की झलक दिखती है। यह मंदिर पारम्परिक कश्मीरी स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें पत्थर की संरचना और जटिल नक्काशी है और

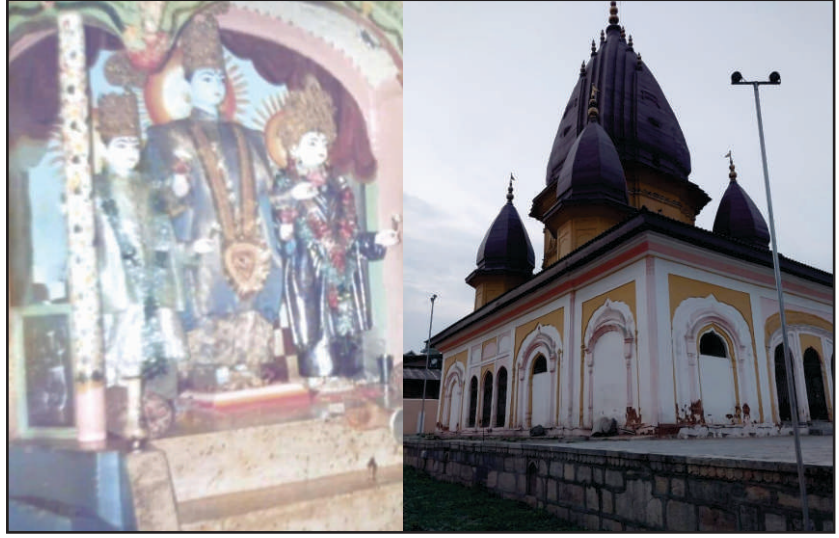
कश्मीरी हिंदू मंदिरों की तरह एकल-शिखर शैली का है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 1585 मीटर (5200 फुट) की ऊंचाई पर स्थित है।

मंदिर के गर्भगृह में भगवान् राम (रघुनाथ) और सीता की मूर्तियां थीं। यह मंदिर डोगरा शासकों की वैष्णव परंपरा और धार्मिक संरक्षण नीति का प्रतीक रहा और कश्मीर में हिन्दू धार्मिक संरचनाओं को सुदृढ़ किया। यहां दैनिक पूजा, आरती और रामायण का पाठ लगातार होता था। रामनवमी और दीपावली जैसे त्योहारों के मौके पर पूजा का विशेष आयोजन किया जाता था और मेला लगता था। पूरे शहर में झांकियां निकलती थी और हर मंदिर या मोहल्ले के अपनी-अपनी झांकियां हुआ करती थीं। श्रीनगर का ऐतिहासिक यह मंदिर कश्मीर में हिंदू धर्म के लोगों के सामाजिक-धार्मिक गतिविधियों के एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था।

इस मंदिर परिसर में स्कूल, धर्मशाला और एक बड़ा पुस्तकालय भी था। मंदिर के पश्चिमी दीवार के पास एक बालिका विद्यालय था जिसका नाम रुपा देवी शारदापीठ स्कूल

लड़कियों का स्कूल था। यह झेलम किनारे स्थित था। स्कूल के पीछे एक थियेटर हॉल था जहां वहां नाटक का मंचन होता था। इस मंदिर परिसर में दो बड़ा मैदान था जहां आसपास के लोग क्रिकेट, फुटबॉल खेलते थे और झेलम नहीं में तैरने के लिए आते थे। पुराने स्थानीय लोग लखते हैं कि रविवार के दिनों में लोग नदी नाव से पारकर मंदिर के विशाल प्रांगण में क्रिकेट खेलने जाया करते थे। इस परिसर का देखभाल दीनानाथ जी किया करते थे। मंदिर के पुस्तकालय में कई अमूल्य पांडुलिपियां और धर्मग्रंथ भी थे।

गौरतलब है कि हब्बा कदल के निकट रघुनाथ मंदिर मोहल्ला है, वहीं कर्णनगर के नजदीक एक स्कूल है जिसका नाम है हाईस्कूल रघुनाथ मंदिर। स्थानीय और पुराने लोग अपने सोशल मीडिया पर इस रघुनाथ मंदिर के बारे में लिखते रहे हैं और वे पुराने दिनों को याद भी करते रहे हैं। झेलम नदी में आने वाले बाढ़ से मंदिर परिसर और धर्मशाला को होने वाली क्षति सहित मंदिर के आस-पास रहने वालों को शिदत से अपने शब्दों में बयां करते हुए लिखते हैं, “नदी के निचले हिस्से में उस गली के बाद पहला घर, जिसे सहारों से टिकाया गया था, एक बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया था. बाढ़ का पानी धर्मशाला के देवघर के मेहराब से थोड़ा ऊपर तक पहुंच गया था और वास्तव में कुछ खिड़कियों से रिस्ते हुए धर्मशाला और भवन के भीतर आ गया। इसके बाद भवन की मरम्मत की गई। भूतल को उसी अवस्था में छोड़ दिया गया और वहां कश्मीरी हस्तशिल्प का एक प्रसिद्ध आउटलेट खोला गया। यहां अक्सर पर्यटक आते थे जो प्रथम पुल (आईएसटी ब्रिज) से सातवें पल तक नाव की सवारी करते थे। दूसरे सहारों से टिकाई गई संरचना में भी कश्मीरी चांदी और धातुशिल्प की कारीगरी की गई थी। बिना सहारे वाले घर एक प्रसिद्ध अभियंता के स्वामित्व में था। इससे दो घर नीचे कोच के घर के आसपास गंजू हाउस का शोरूम था, जो कश्मीरी कालीनों के व्यापार



घाटी के रघुनाथ मंदिर का निर्माण कार्य वर्ष 1835 में महाराज गुलाब सिंह ने शुरू की थी, उनके निधन के बाद यह काम उनके पुत्र और जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराज रणबीर सिंह ने की और यह 1860 में बनकर तैयार हुआ। यह मंदिर झेलम नदी के बाएं तरफ है और यह मंदिर पहाड़ की चोटी यानी शिखर की शैली में बना हुआ है। इसमें जम्मू के रघुनाथ मंदिर परिसर की वास्तुकला शैली की झलक दिखती है। यह मंदिर पारम्परिक कश्मीरी स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें पत्थर की संरचना और जटिल नक्काशी है और कश्मीरी हिंदू मंदिरों की तरह एकल-शिखर शैली का है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 1585 मीटर (5200 फुट) की ऊंचाई पर स्थित है।

और निर्माण के अग्रदूत माने जाते थे। मंदिर की दीवार के किनारे कौल, मोजा और राजदान परिवारों के घर थे।

मंदिर की स्थिति को लेकर सुनील टिक्कू अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखते हैं- रघुनाथ मंदिर की जर्जर स्थिति की ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मुझे पांच वर्ष लग गए। स्थानीय निवासियों, जिन्होंने इस क्षेत्र के पंडितों के घर खरीद लिए थे, उन्होंने मंदिर को कूड़ा घर में बदल दिया था। सुनील टिक्कू स्थानीय मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष हैं, जिसके अध्यक्ष भरत शर्मा हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि कश्मीरी पंडित एम.के. राजदान ने मंदिर समिति के सहयोग से मंदिर के आसपास के समस्त

कचरे को हटवाया।

वर्ष 2020 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस मंदिर के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया। जम्मू-कश्मीर पर्यटन विभाग ने रेनोवेशन प्रोजेक्ट के लिए भारतीय राष्ट्रीय कला और संकसरिति ट्रस्ट (इंटेक) का सहयोग लिया और मंदिर का जिम्मा संभालने वाली समिति ने भव्य रामनवमी के साथ मंदिर के पुनः उद्घाटन का आयोजन किया। गौरतलब है कि भगवान् राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्ति बनाने के आदेश पश्चिम बंगाल के कोलकाता के कारीगरों को दिए गए हैं और मूर्ति मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण होने पर स्थापित किया जायेगा।



गर्म हवा का गुंबद बढ़ाता धरती का तापमान



प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार

दे श के कई राज्यों में वायुमंडल में अंगड़ाई ले रही गर्म हवाओं ने अप्रैल माह में ही तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा दिया है। मौसम की जानकारी देने वाली निजी एजेंसी स्काई मेट के अनुसार इसका मुख्य कारण केवल सामान्य मौसमी बदलाव न होकर वह उष्मा का बन जाने वाला छत्रीनुमा गोला है, जो आधे भारत के राज्यों में मंडरा रहा है। इस समय दिल्ली, उप्र, राजस्थान, हरियाणा, मप्र, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना में गर्मी एकाएक बढ़ गई है। इस प्राकृतिक स्थिति को उष्मा का क्षत्रप (हीट डोम) या गुंबद कहा जा

रहा है। यह क्षत्रप तब बनता है, जब वायुमंडल में उच्च दबाव की एक प्रणाली लंबे समय तक किसी एक क्षेत्र में ठहर जाती है। दरअसल यह एक बर्तन के ढक्कन की तरह गर्म हवा को नीचे धरती की तरफ दवाएं रखती है, जो तेज गर्मी का कारण बन जाती है। नतीजतन ऐसे क्षेत्रों में तापमान खतरनाक ढंग से बढ़ जाता है और कई दिनों या हफ्तों तक भीषण गर्मी या लू बनी रहती है।

भारतीय मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान ने इस संकट को और बढ़ाने के संकेत दिए हैं। अगले कुछ दिनों में उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के ज्यादातर हिस्सों में भीषण लू के रूप में गर्म हवाएं चलने की आशंका है। इस बार गर्मी का मिजाज इसलिए भी अलग है, क्योंकि कई तटीय इलाकों और मैदानी क्षेत्रों में नमी वाली गर्मी यानी उमस का असर भी देखने में आ रहा है। इससे लू लगने का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। आजकल आधे भारत में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है, जो लोगों को पस्त कर रहा है।

अतएव हरेक जुबान पर प्रचंड धूप और गर्मी जैसे बोल आमफहम हो गए हैं। हालांकि लू और प्रचंड गर्मी के बीच भी एक अंतर होता है। गर्मी के मौसम में ऐसे क्षेत्र जहां तापमान, औसत तापमान से कहीं ज्यादा हो और पांच दिन तक यही स्थिति यथावत बनी रहे तो इसे 'लू' यानी गर्मी का गोला कहने लगते हैं। मौसम की इस असहनीय विलक्षण दशा में नमी भी समाहित हो जाती है। यही सर्द-गर्म थपेड़े लू की पीड़ा और रोग का कारण बन जाते हैं। किसी भी क्षेत्र का औसत तापमान, किस मौसम में कितना होगा, इसकी गणना एवं मूल्यांकन पिछले 30 साल के आंकड़ों के आधार पर की जाती है। वायुमंडल में गर्म हवाएं आमतौर से क्षेत्र विशेष में अधिक दबाव की वजह से उत्पन्न होती हैं। वैसे तेज गर्मी और लू पर्यावरण और बारिश के लिए अच्छी होती हैं। अच्छा मानसून इन्हीं आवारा हवाओं का पर्याय माना जाता है, क्योंकि तपिश और बारिश में गहरा अंतर्संबंध है।

धूप और लू के इस जानलेवा संयोग से कोई व्यक्ति पीड़ित हो जाता है, तो उसके

लू उतारने के इंतजाम भी किए जाते हैं। दरअसल लू सीधे दिमागी गर्मी को बढ़ा देती है। अतएव इसे समय रहते ठंडा नहीं किया तो यह बिगडा अनुपात व्यक्ति को बौरा (पागल) भी सकता है। वैसे शरीर में प्राकृतिक रूप से तापमान को नियंत्रित करने का काम मस्तिष्क में 'हाइपोथैलेमस' अर्थात 'अधश्चेतक' क्षेत्र करता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य पियूष ग्रंथी के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी प्रक्रिया के माध्यम से तापमान को संतुलित बनाए रखना होता है। इसे चिकित्साशास्त्र की भाषा में हाइपर-पीरेक्सिया कहते हैं। यानी शरीर के तापमान में असमान वृद्धि या अधिकतम बुखार का बढ़ जाना। इसकी चपेट में बच्चे और बुजुर्ग आसानी से आ जाते हैं।

बाहरी तापमान जब शरीर के भीतरी तापमान को बढ़ा देता है, तो हाइपोथैलेमस तापमान को संतुलित बनाए रखने का काम नहीं कर पाता। नतीजतन शरीर के भीतर बढ़ गई अनावश्यक गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है, जो शरीर में लू का कारण बन जाती है। इस स्थिति में शरीर में कई जगह प्रोटीन जमने लगता है और शरीर के कई अंग एक साथ निष्क्रियता की स्थिति में आने लग जाते हैं। ऐसा शरीर में पानी की कमी यानी डी-हाइड्रेशन के कारण भी होता है। दोनों ही स्थितियां जानलेवा होती हैं। इस स्थिति के निर्माण हो जाने पर बुखार उतारने वाली साधारण गोलियां काम नहीं करती हैं। क्योंकि ये दवाएं दिमाग में मौजूद हाइपोथैलेमस को ही अपने प्रभाव में लेकर तापमान को नियंत्रित करती हैं। जबकि लू में यह स्वयं शिथिल होने लग जाता है।

हवाएं गर्म या आवारा हो जाने का प्रमुख कारण ऋतुचक्र का उलटफेर और भूतापीकरण (ग्लोबल वार्मिंग) का औसत से ज्यादा बढ़ना है। इसीलिए वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि इस बार प्रलय धरती से नहीं आकाशीय गर्मी से आएगी। जिस आकाश को हम निरीह और खोखला मानते हैं, परंतु वास्तव में यह खोखला है नहीं। भारतीय दर्शन में इसे पांचवां तत्व यूं ही नहीं माना

गया है। सच्चाई है कि यदि परमात्मा ने आकाश तत्व की उत्पत्ति नहीं की होती, तो संभवतः आज हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। हम श्वास भी नहीं ले पाते। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये चारों तत्व आकाश से ऊर्जा लेकर ही क्रियाशील रहते हैं। ये सभी तत्व परस्पर परावलंबी हैं। यानी किसी एक तत्व का वजूद क्षीण होगा तो अन्य को भी छीजने की इसी अवस्था से गुजरना होगा। प्रत्येक प्राणी के शरीर में आंतरिक स्फूर्ति एवं प्रसन्नता की अनुभूति आकाश तत्व से ही संभव होती है, इसलिए इसे ब्रह्मतत्व भी कहा गया है। अतएव प्रकृति के संरक्षण के लिए सुख के भौतिकवादी उपकरणों से मुक्ति की जरूरत है। क्योंकि हम देख रहे कि कुछ एकाधिकारवादी देश भूमंडलीकरण का मुखौटा लगाकर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन

भारतीय मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान ने इस संकट को और बढ़ाने के संकेत दिए हैं। अगले कुछ दिनों में उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के ज्यादातर हिस्सों में भीषण लू के रूप में गर्म हवाएं चलने की आशंका है। इस बार गर्मी का मिजाज इसलिए भी अलग है, क्योंकि कई तटीय इलाकों और मैदानी क्षेत्रों में नमी वाली गर्मी यानी उमस का असर भी देखने में आ रहा है। इससे लू लगने का खतरा और अधिक बढ़ जाता है।

से दुनिया की छत यानी ओजोन परत में छेद को चौड़ा करने में लगे हैं। यह छेद जितना विस्तृत होगा वैश्विक तापमान उसी अनुपात में अनियंत्रित व असंतुलित होगा। इस बढ़े तापमान का प्रभाव जिन-जिन क्षेत्रों में पड़ेगा, वहां खेत बंजर हो जाएंगे। पालतू मवेशी और वनजीव गर्मी से तड़प-तड़प कर प्राण छोड़ने

लग जाएंगे, जो मानव समुदाय अभावग्रस्त हैं, उन पर गर्म हवाओं का यह दबाव कहर बनकर टूटेगा। यह जानलेवा भी साबित होगा।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2020 में किए गए एक अध्ययन से स्पष्ट हुआ था कि जलवायु परिवर्तन और पानी का अटूट संबंध है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशिया को 2030 तक बाढ़ों की कीमत प्रत्येक वर्ष चुकानी पड़ेगी। इनसे करीब सालाना 15.6 लाख करोड़ की हानि उठानी पड़ सकती है। साफ है, वैश्विक तापमान के बढ़ते खतरे ने आम आदमी के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। दुनिया में कहीं भी एकाएक बारिश, बाढ़, बर्फबारी, फिर सूखे का कहर यही संकेत दे रहे हैं। आंधी, तूफान और फिर यकायक ज्वालामुखियों के फटने की हैरतअंगेज घटनाएं भी यही संकेत दे रही हैं कि अदृश्य खतरे इर्द गिर्द ही कहीं मंडरा रहे हैं। समुद्र और अंटार्कटिका जैसे बर्फीले क्षेत्र भी इस बदलाव के संकट से दो-चार हो रहे हैं। दरअसल वायुमंडल में अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड महासागरों में भी अवशोषित होकर गहरे समुद्र में बैठ जाती है। यह वर्षों तक जमा रहती है। पिछली दो शताब्दियों में 525 अरब टन कचरा महासागरों में विलय हुआ है। इसके इतर मानवजनित गतिविधियों से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का 50 फीसदी भाग भी समुद्र की गहराइयों में समा गया है। इस अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड के जमा होने के कारण अंटार्कटिका के चारों ओर फैले दक्षिण महासागर में इस कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की क्षमता निरंतर कम हो रही है। इस स्थिति का निर्माण खतरनाक है। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के मुताबिक वैज्ञानिकों का कहना है कि दक्षिण महासागर में कार्बन डाइऑक्साइड से लबालब हो गया है। नतीजतन अब यह समुद्र इसे अवशोषित करने की बजाय वायुमंडल में ही उगलने लग गया है। अगर इसे जल्दी नियंत्रित नहीं किया गया तो वायुमंडल का तापमान तेजी से बढ़ेगा, जो न केवल मानव प्रजाति, बल्कि सभी प्रकार के जीव-जंतुओं के अस्तित्व के लिए खतरनाक होगा।



बच्चों की छुट्टियां कैसे दिलचस्प बनाएं



पूनम भटनागर
लेखिका

छुट्टियां चीज ही ऐसी हैं कि नाम सुनते ही सभी उत्साहित हो जाते हैं, पर बच्चे समय से कोई काम कर ही नहीं पाते और अपना दिमाग बेकार के विषयों में लगा देते हैं पर ये क्या नमिता जी के यहां तो छुट्टियों के पहले दिन ही युद्ध का माहौल छाया हुआ है। सोनल और राजू तो हाथापाई पर उतर आए। नमिता जी बार बार बीच बचाव करके जाती, पर थोड़ी ही देर में स्थिति वैसी ही बन जाती। अब के बारे भी वह रसोई का काम छोड़कर हांफते हुए आई और दोनों की कथा सुनने लगीं और दोनों को इंस्ट्रक्शन दिया पर ये क्या इस सब में रसोई

में गैस पर चढ़ाई सब्जी जलने की खुशबू आई, तो वह किचन की तरफ भागी, पर उनके जाते ही फिर बहस शुरू हो गई। खैर उस समय तो किसी तरह बिता कर उन्होंने बच्चों को शांत किया पर वह सोचने लगी कि सारी छुट्टियां तो वह इस माहौल को घर में बना कर नहीं रख सकतीं। तभी उन्होंने अपनी सहेली रोशनी को फोन किया और उसके साथ अपनी प्रोब्लम बताई तो रोशनी ने उन्हें बच्चों के छुट्टियां बिताने के कई टिप्स दिए जो हम आपके साथ साझा करते हैं।

पहले तो यह देखिए आपका बच्चा किसी आयु, वर्ग में आता है, फिर यदि वह

3-5 वर्ष में आता है तो उसके साथ आपको मेहनत करनी होगी। उसे अपना थोड़ा समय दीजिए।

उसे शिष्टाचार सूचक शब्दों से अवगत कराएं। धन्यवाद, सौरी गलती करने पर उसे मानना। इसके अलावा उनके स्वास्थ्य संबंधी आदत का विकास करने वाली बातें बताना।

1. बच्चों को साफ सुथरा रहने के लिए सिखाया जाये। इसके लिए उन्हें रोज दांत साफ करना बताएं। रोज नहाने के लिए उन्हें कहानी सुनाएं कि हवा में धूल के कण होते हैं, जिनमें जर्म होते हैं यदि, हम अपने शरीर को साफ नहीं रखेंगे, तो बिमारियां घेर लेंगी और

इसके लिए रोज स्नान आवश्यक है। अपने हाथों को स्वच्छ रखें।

ये तो हुई गुणात्मक बातें, इसके अलावा उन्हें प्राकृतिक जानवरों व पशु पक्षियों की कहानियों से अवगत कराया जाना चाहिए। खेल खिलौने से मिलकर कैसे खेला जाए, यह बताएं। कलर्स की, काउंटिंग, अक्षर ज्ञान खेल में ही उन्हें आ जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। स्वयं भोजन करने को उन्हें प्रेरित करें।

2. 6-12 वर्ष की आयु वर्ग के लिए। इसमें थोड़े बड़ी आयु के बच्चे आ जाते हैं, जैसे तो इस आयु में बच्चे थोड़े समझदार हो जाते हैं पर फिर भी कहते हैं न कि जहां दो बच्चे साथ बैठे तो लड़ना झगड़ना तो संभव ही है, तो इसके लिए क्यों न छुट्टियों के इस माहौल में इन्हें खेल खेल में ही कुछ शिक्षाप्रद सिखा दें इस आयु वर्ग के बच्चों को हम थोड़े बड़े काम करने के लिए दे सकते हैं जैसे इन्हें टाइम की वैल्यू समझाएं। दिन के समय को किस तरह व्यतीत करना है, यह जानकारी रखें। किस तरह टाइम खेल के साथ कुछ किरियेटिव करने में लगाना है, यह जानें। कुकिंग में शौक है तो सैंडविच, ब्रेड स्लाइस, सलाद आदि बनाना सीख सकते हैं। अपना बिस्तर बनाना, व तय करके रखना। अपने कपड़े तय करना, जूते पोलिश करना।

स्वच्छता में अपने कमरे को स्वच्छ रखना। इस उम्र से पैसे की समझ भी आने लगती है

पैसे गुल्लक में जमा करना। उन्हें किस तरह व कितना खर्च करना है ये जानना। पालतू जानवर को खाना देना। और उनकी देखभाल करना। गमलों में पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना। तार्किक क्षमता बढ़ाने के लिए पजल और पहेलियां सुलझाना। दोस्तों के साथ कठपुतली, व नाटकों का आयोजन करना। इसके अलावा म्यूजिक व डांस सीखना।

3. इससे बड़ी उम्र के बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं व उनमें जाकर स्पोर्ट्स की, म्यूजिक की, इंस्ट्रुमेंट बजाने की या कोई



परिक्षा की तैयारी की बाकायदा ट्रेनिंग ले सकते हैं।

मोहित ऐसे ही स्कूल से सीख कर एक गिटार वादक बना। आज वह कितनी ही प्रतियोगिताओं में नाम कमा चुका है। छोटी सी उम्र में प्रसिद्ध हो गया। इन सबके अलावा इस उम्र में जीवन के क्या वैल्यू होते हैं, बड़ों की किस तरह रिस्पेक्ट की जाती है, यह भी सिखाना चाहिए। दयालुता और मदद करने का गुण भी उनके अंदर विकसित करना चाहिए। केशव इसी उम्र का बच्चा है वह ग्राउंड में खेल रहा होता है, तभी सामने के घर में रहने वाले दादाजी बाजार से कई बार सामान ला रहे होते हैं। वह सामान उनके हाथ से ले कर घर तक पहुंचाने में उनकी मदद करता है। उसकी देखा-देखी अन्य बच्चों में भी यह गुण आ गया है।

भाषा के लिए कहानी पढ़ कर अंत बदलना या उसको अपनी रचनात्मकता का पुट देकर अपनी भाषा में लिखना। इससे भाषा पर पकड़ मजबूत होगी। और अपने विचारों को व्यक्त करने की तवज्जों मिलेगी।

यह तो हुई गुणात्मक और रचनात्मक कार्य सिखाने की बातें, पर बच्चों का मनोरंजन भी अनिवार्य है तो उनके सैर सपाटे का भी ध्यान रखना चाहिए, क्यों कि अभी छुट्टियां है, बच्चे हर समय तो ज्ञान के वातावरण में नहीं रह सकते, उन्हें कहीं सैर सपाटे के लिए ले जाएं। निम्नलिखित जगहों पर जा सकते हैं

1. उन्हें प्रकृति के करीब , नेशनल वन्य पार्क, जिम कॉर्बेट ले जा सकते हैं जिसमें वह प्राकृतिक वातावरण से जुड़ेगे।
 2. नैनीताल, उत्तराखंड -नैनी झील में बोटिंग व सैर।
 3. दार्जिलिंग, पश्चिम, बंगाल - काम ट्रेन की सवारी।
 4. आगरा का ताजमहल, झांसी का किला, फतेहपुर सीकरी।
 5. कानपुर का ब्लू बर्ड थीम, लखनऊ का पार्क।
 6. मनाली हिमाचल प्रदेश में हिल स्टेशन पर रोहतांग पास में बर्फ से खेलना
 7. उटी, यहां काम ट्रेन की सवारी करना।
 8. बिचेज, गोवा के, मुंबई के तट और अंडमान के समुद्री तट।
 9. जयपुर के व राजस्थान के किले।
 10. दिल्ली का कुतुब मीनार, संग्रहालय और अनेक दर्शनीय स्थल।
- तो देखा आपने बच्चों को तर्क संगत बातें सिखाकर, छुट्टियों में उनका मनोबल तो बढ़ाया ही जा सकता है साथ ही उनके अंदर अच्छी आदतें भी विकसित होती हैं, समय का सदुपयोग तो होता ही है और छुट्टियां बड़ों के लिए भी सिरदर्द न होकर एक दिलचस्प मुद्दा बन जाती है। जरूरत है थोड़े सिकल और समझदारी के साथ उपाय अपनाने की। इन सारे प्लान को अपना कर देखिए आपके बच्चों की छुट्टियां दिलचस्पी का सबब बन जाएंगी।

काशी में विश्व की प्रथम 'विक्रमादित्य वैदिक घड़ी' हुई स्थापित

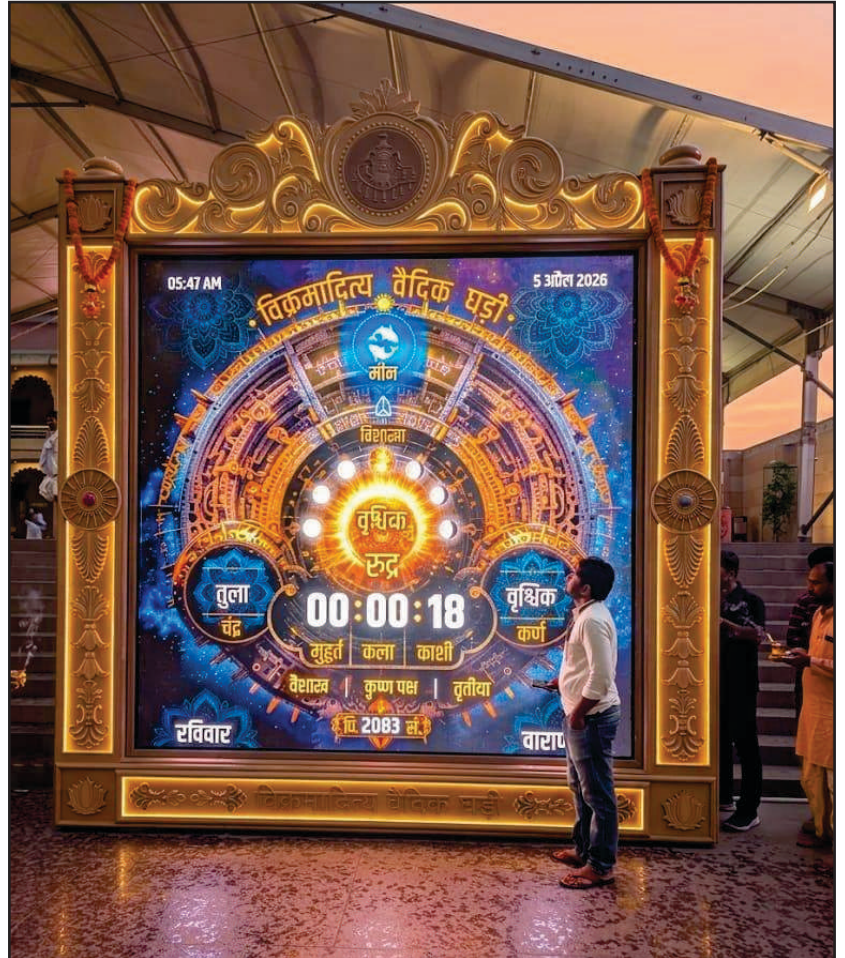


डॉ. मयंक चतुर्वेदी
वरिष्ठ पत्रकार

जब समय सूर्य की गति, नक्षत्रों की चाल और ब्रह्मांड की लय में पढ़ा जाता था, तब भारत अपनी कालदृष्टि से विश्व को संचालित कर रहा था। आज वही दृष्टि पुनः सजीव होकर इतिहास के दो सबसे प्राचीन और जीवंत नगरों उज्जैन और वाराणसी के संगम से एक नई सांस्कृतिक चेतना का संचार कर रही है। ऐसे समय में इतिहास भी पुनर्जीवित हो उठा है।

दरअसल, आज बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में स्थापित 'विक्रमादित्य वैदिक घड़ी' भारत की प्राचीन कालगणना परंपरा का पुनर्जन्म ही तो है, एक ऐसा पुनर्जागरण, जो अतीत की वैज्ञानिकता को वर्तमान की तकनीक से जोड़ता है। यह क्षण बता रहा है कि भारत में समय सृजित की निरंतर यात्रा है। मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की विशेष पहल पर, भारतीय कालगणना पर आधारित विश्व की प्रथम 'विक्रमादित्य वैदिक घड़ी' को उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है।

बाबा काशी विश्वनाथ को अर्पित इस



घड़ी को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तीन अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को भेंट की थी। इसके पश्चात, विक्रम संवत् 2083, वैशाख कृष्ण पक्ष की द्वितीया (4 अप्रैल, 2026) को इसे मंदिर परिसर में पूर्ण श्रद्धा और विधि-विधान के साथ स्थापित किया गया। यह मध्यप्रदेश सरकार के उस संकल्प की ओर एक बड़ा कदम है, जिसके तहत देश के सभी ज्योतिर्लिंगों और अयोध्या के श्री राम मंदिर

में भी वैदिक घड़ी की स्थापना की जानी है।

उज्जैन से काशी यानी काल और मोक्ष का संवाद : भारतीय संस्कृति में उज्जैन को 'काल की राजधानी' और वाराणसी को 'मोक्ष की नगरी' कहा जाता है। उज्जैन वह केंद्र रहा है, जहां से प्राचीन काल में समय की गणना की जाती थी, जहां से ज्योतिष, खगोल और पंचांग की परंपराएं पूरे भारत में प्रसारित होती थीं। दूसरी ओर, काशी वह धाम है जहां जीवन अपने अंतिम

सत्य से साक्षात्कार करता है। ऐसे में जब उज्जैन की कालगणना काशी के विश्वनाथ धाम में पहुंचती है, तब यह तकनीकी यंत्र स्थापना काल और मोक्ष के शाश्वत संवाद का प्रतीक बन जाती है।

‘विक्रमादित्य वैदिक घड़ी’ को महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा विकसित किया गया है। यह घड़ी आधुनिक डिजिटल तकनीक और प्राचीन वैदिक ज्ञान का अद्भुत समन्वय है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह सूर्योदय के साथ संचालित होती है, अर्थात् इसका हर क्षण प्रकृति के साथ तालमेल में चलता है।

भारतीय कालगणना के अनुसार एक दिन को 30 मुहूर्तों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक मुहूर्त का अपना विशेष महत्व होता है, कहीं वह शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त होता है, तो कहीं साधना के लिए। यह घड़ी न केवल मुहूर्त बताती है, बल्कि तिथि, नक्षत्र, योग, करण और भद्रा जैसी सूक्ष्म जानकारियाँ भी प्रदान करती है। यह वही वैज्ञानिक प्रणाली है, जिसे आधुनिक विज्ञान आज ‘कॉस्मिक टाइमिंग’ के रूप में समझने का प्रयास कर रहा है।

भारतीय कालगणना : वेदों से विज्ञान तक : भारतीय कालगणना की जड़ें वेदों, उपनिषदों और सिद्धांत ज्योतिष में निहित हैं। यहां समय को ‘काल’ कहा गया है, जिसे सृष्टि का आधार माना जाता है। ‘महाकाल’ हमें यह सिखाते हैं कि समय ही सृजनकर्ता है और वही संहारक भी। प्राचीन भारत में उज्जैन को शून्य रेखा (Prime Meridian) माना जाता था। यहीं से ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की चाल और ऋतुओं का निर्धारण किया जाता था। यह ज्ञान इतना सटीक था कि आज भी भारतीय पंचांग के आधार पर किए गए ज्योतिषीय गणना के परिणाम आश्चर्यजनक रूप से सटीक होते हैं।



आज बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में स्थापित ‘विक्रमादित्य वैदिक घड़ी’ भारत की प्राचीन कालगणना परंपरा का पुनर्जन्म ही तो है, एक ऐसा पुनर्जागरण, जो अतीत की वैज्ञानिकता को वर्तमान की तकनीक से जोड़ता है। यह क्षण बता रहा है कि भारत में समय सृजित की निरंतर यात्रा है। मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की विशेष पहल पर, भारतीय कालगणना पर आधारित विश्व की प्रथम ‘विक्रमादित्य वैदिक घड़ी’ को उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है।

आधुनिक युवा और प्राचीन जड़ें: आज की पीढ़ी, जो डिजिटल युग में पली-बढ़ी है, समय को सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर देखती है। ऐसे में यह वैदिक घड़ी उन्हें उस गहराई से परिचित कराएगी, जहां समय केवल ‘घंटा-मिनट’ तक सीमित न होकर ‘ऊर्जा और चेतना’ का प्रवाह है। यह घड़ी

युवाओं को यह समझने का अवसर देगी कि भारत का विज्ञान वर्तमान में भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना कि कभी अतीत में रहा है। यह उन्हें अपनी जड़ों की ओर लौटने के लिए प्रेरित करेगी, जहां ज्ञान जानकारी से कहीं अधिक अनुभव रहा है।

प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण और राष्ट्रीय विस्तार : उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 29 फरवरी 2024 को उज्जैन में इस घड़ी का लोकार्पण किया गया था। अब काशी में इसकी स्थापना, इस पहल को राष्ट्रीय स्वरूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह दिखाता है कि भारत आधुनिकता की ओर बढ़ने के साथ ही अपनी जड़ों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। इस तरह से काशी और उज्जैन का यह संगम, भारतीय संस्कृति के उस गहरे सत्य को उजागर करता है, जहां समय बीतता नहीं, वह चेतना को दिशा देता है। ‘विक्रमादित्य वैदिक घड़ी’ इस सत्य का आधुनिक प्रतीक है, यह हमें याद दिलाते रहने के लिए है कि हमारी परंपराएं अतीत की स्मृति में सुख देती और दिशा देती हैं और वर्तमान के साथ भविष्य के लिए भी अनेक संभावनाएं पैदा करती हैं।

यह पहल एक ऐसे भारत की तस्वीर प्रस्तुत करती है, जो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, अपनी परंपराओं पर गर्व करता है और उन्हें आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर विश्व के सामने एक नई राह प्रस्तुत करता है। यहां समय घड़ी की टिक-टिक नहीं, बल्कि एक अनंत यात्रा है, जिसमें हर क्षण, हर मुहूर्त, जीवन के अर्थ को और अधिक गहराई से समझने का अवसर बन जाता है। इस घड़ी के माध्यम से श्रद्धालु और युवा पीढ़ी न सिर्फ भारतीय मानक समय (आईएसटी) जान सकेंगे, बल्कि पंचांग, तिथि, योग, नक्षत्र, भद्रा स्थिति और ग्रहों के गोचर जैसी सूक्ष्म जानकारियों से भी खबर हो सकेंगे।

श्रीसेतु मन्दिरम की बारी सन्निकट



नरेन्द्र भदौरिया
वरिष्ठ पत्रकार

श्री राम की सेना द्वारा पुरुषार्थ से निर्मित श्रीसेतु मन्दिरम को आस्था के बड़े केन्द्र के रूप में विकसित करने की बारी अब सन्निकट है। सनातन संस्कृति की इस अप्रतिम धरोहर की अन्तर राष्ट्रीय मान्यता सर्व स्वीकार्य है। इसी को आधार मानते हुए भारत ने श्रीरामेश्वरम में सागर की लहरों की केलि के बीच सुषुप्त पड़े सेतुबन्ध की ऐतिहासिकता को उजागर करने की योजना पर काम शुरू करने का निर्णय किया है। कुछ बड़े विज्ञानियों विशेषज्ञों के संयुक्त दल द्वारा इस सन्दर्भ में अन्वेषण करके रिपोर्ट देने की प्रतीक्षा की जा रही है।

अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेंसी नासा के जेमिनी -11 उपग्रह ने अन्तरिक्ष से 1966 में भारत और श्रीलंका के बीच एक सेतु बन्ध की अनेक तस्वीरें ली थीं। उच्च कोटि के कैमरों से लिये गये इन चित्रों का गहराई से अमेरिकी विज्ञानियों ने अध्ययन करके रिपोर्ट दी थी।

इस प्रक्रिया में अमेरिकी विज्ञानियों ने कोई त्रुटि नहीं रहे इसलिए नासा के तीन और उपग्रहों को भारत के रामेश्वरम क्षेत्र से श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट के मन्नार द्वीप के बीच सागर में बनी आकृति का कई बार आकलन किया। जिससे सारी स्थिति स्पष्ट हो गयी कि यह रचना हजारों वर्ष पहले मानव द्वारा निर्मित है अर्थात् प्राकृतिक संरचना नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति को इस अति महत्वपूर्ण अन्वेषण की जानकारी नासा ने 1990 में दी थी। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर जॉर्ज हर्बर्ट वाकर बुश विराजमान थे। नासा के

विज्ञानियों ने बुश को बताया कि भारत श्रीलंका के मध्य स्थित समुद्री क्षेत्र को मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। मन्नार द्वीप लंका के आधिपत्य में है। जबकि रामेश्वरम द्वीप भारत का है। यह खाड़ी हिन्द महासागर का अंश है। यहां सागर का अन्तर तल उथला है। इसी क्षेत्र में 48 किमी की लम्बाई और तीन किमी से अधिक की चौड़ाई में मानव सभ्यता की एक अनमोल निशानी छिपी पड़ी है। रामेश्वरम और मन्नार द्वीप के बीच की इस खाड़ी के क्षेत्र में हजारों वर्षों की अवधि में समुद्री फैलाव कई बार फैलता और सिकुड़ता रहा है। इसकी पुष्टि करते हुए विज्ञानियों ने बताया कि



वर्तमान समय में रामेश्वरम और मन्नार तट के मध्य सागर की दूरी केवल 48 किमी रह गयी है। हजारों वर्षों के अन्तराल में यह खाड़ी एक हजार किमी से अधिक विस्तार में फैली होने के साक्ष्य भी यहां मौजूद हैं।

समुद्र का यही भाग विशाल बाँधनुमा एक रचना को संजोये हुए है। यह रचना विशेष प्रकार के पत्थरों से गढ़ी गयी है। यह मानव निर्मित है। समुद्र की ऊपरी सतह से बिल्कुल सटी है। चार से आठ मीटर तक प्राकृतिक थपेड़ों से यह रचना कहीं कहीं धंस गयी है। इसकी सतह 45 स्थलों पर लहरों के बीच प्रायः साफ दिख जाती है। नासा के अध्ययन में यह भी कहा गया है कि श्रीरामेश्वरम तट के निकट स्थित धनुष कोटि से यह रचना हजारों वर्ष पूर्व बनी होगी। कहीं दूरस्थ स्थलों के ज्वालामुखी पर्वत के पत्थरों को लाकर इसे

निर्मित किया गया होगा। जिसे सन 1480 में आयी भीषण सुनामी की लहरों ने बहुत हानि पहुंचायी। इसके बाद भी यह क्षेत्र सुनामी प्रभावित रहा। इसीलिए यहां पम्बन रामेश्वर द्वीप के बड़े भूभाग से समुद्र सिकुड़ गया। भूमि का भाग बढ़ गया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण धनुष कोटि का क्षेत्र है। जहां भारत ने पर्यटन हेतु नया निर्माण भी किया है।

जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश ने नासा के विज्ञानियों से उस समय पूछा कि इस शोध से अमेरिका और पश्चिम के देशों को क्या लाभ होगा। नासा के विज्ञानी अपने राष्ट्रपति के इस तर्क के उत्तर में तब केवल इतना कह सके कि यह सेतु पृथ्वी पर मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन प्रमाण है। इसलिए यह अति महत्व का है।

थोरियम के प्रचुर भण्डार का क्षेत्र : संयुक्त राज्य अमेरिका के 42 वें राष्ट्रपति के रूप में 20 जनवरी 1993 में बिल क्लिंटन ने शपथ ली। उनके कार्यकाल में रामसेतु को दुनिया के सामने उजागर करने का अवसर नासा को मिल पाया। क्लिंटन ने इस अनुसंधान के लिए नासा के विज्ञानियों की सराहना की। तब यह रिपोर्ट अमेरिका और अन्य देशों की मीडिया में सुर्खियों के साथ प्रकाशित होने लगी। उस समय नासा ने एक और बड़ा खुलासा यह किया कि इस सेतुबन्ध के समुद्री क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में थोरियम खनिज का भण्डार है जो यूरेनियम का सशक्त विकल्प है।

भयवश शुरू हुआ विरोध : श्रीरामसेतु का अस्तित्व प्रमाणित होने का समाचार जब भारत पहुंचा तो यहां कांग्रेस की सरकार थी। पामुलपार्थी व्यंकट नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। वह 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहे। रामसेतु के अस्तित्व का वैज्ञानिक प्रमाण मिलने पर भारत में सनातन संस्कृति को मानने वाले हिन्दुओं के सभी पन्थों वर्गों में उमंग की लहर दौड़ गयी। श्रीराम की ऐतिहासिकता के एक प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में श्रीरामसेतु को देखा जाने लगा। इससे भारत के हिन्दू विरोधी

समुदायों से अधिक राजनीतिक दलों को अपनी नींव खिसकती लगी। गैर हिन्दू सम्प्रदायों-विशेष कर मुस्लिम और ईसाई समुदाय कांग्रेस और अन्य अहिन्दू समर्थक दलों को झकझोरने लगे। कांग्रेस केन्द्र की सत्ता पर आसीन थी। नरसिंहराव के बाद इटली मूल की हिन्दुओं की कट्टर विरोधी सोनिया के हाथों में अप्रत्यक्ष सत्ता केन्द्रित हो गयी थी। सोनिया को लगा कि इससे तो भारत में सनातन हिन्दू संस्कृति को रौंदने का उनका एजेण्डा धरा रह जाएगा। सनातनी हिन्दू समाज बहुत शक्तिशाली बन कर संगठित होगा।

सोनिया के कहने पर कांग्रेस के पी चिदम्बरम सहित कई नेताओं ने नेहरू के समय की एक फाइल खोज निकाली। यह फाइल 1956 की थी। जिसमें नेहरू ने श्रीलंका और भारत के बीच समुद्र के निचले तल को गहरा करके बड़े जहाजों को आर पार जाने का रास्ता बनाने की योजना गढ़ी थी। बात 1956 की है। तब तक श्रीरामसेतु के अस्तित्व की बात श्रीराम भक्तों के मानस में रामायण और अन्य हिन्दू ग्रन्थों के वर्णन तक सीमित थी। यही कि इस समुद्र में श्रीरामसेतु समुद्र की लहरों के नीचे बना होगा। जो हजारों वर्ष बाद अब होगा भी तो भग्न खण्डहरों तक सीमित होगा। पर नासा की रिपोर्ट ने हिन्दू समाज के भीतर श्रद्धा के एक बड़े ज्वार को जगा दिया था।

सोनिया के इशारे पर रामसेतु तोड़ा जाना था : सोनिया को लगा कि उनके हाथ एक बड़ा अवसर आ गया है। नासा कुछ भी कहे वह समुद्र में बनी इस रचना (रामसेतु) को तोड़ कर मिटा देंगी। इससे मुस्लिम और ईसाई शक्तियाँ उनकी पार्टी को फिर जिताती रहेंगी। तमिलनाडु की द्रमुक सरकार से मिलकर केन्द्र सरकार ने आनन-फानन में रूस की एक कम्पनी को श्रीरामसेतु तोड़ने का ठेका दे दिया। रूस की बड़ी मशीनें श्रीरामसेतु को तोड़ने पहुंच गयीं। एक विराट रूसी मशीन ने उक्त सेतु के निकट एक बड़ी चट्टान जो सेतु से सटी थी उस पर भरपूर जोर लगाया। तभी एक तेज धमाके से साथ इस मशीन के दो टुकड़े हो गए। तीन रूसी तकनीशियन गम्भीर रूप से घायल हो गये। जिन्हें बचाकर निकालने में समय लगा। इस घटना से श्रीरामसेतु को तोड़ने आया रूसी दल लौट गया। वह टूटी

मशीन वहीं छोड़ कर चलता बना।

विहिप की अगुवाई में आन्दोलन: विश्व हिन्दू परिषद की अगुवाई में हिन्दुओं के कई संगठन खुलकर मैदान में डट गये। दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ जिसमें लाखों लोग पहुंचे। कांग्रेस सरकार को हिन्दुओं की ओर से कोर्ट में घसीटा गया तो सोनिया ब्रिगेड एक बड़ी चूक कर बैठी। न्यायालय में कांग्रेस सरकार ने शपथ पत्र दिया। जिसमें श्रीराम के अस्तित्व को काल्पनिक कहा गया। श्रीराम और उसने जुड़े सारे चरित्र एक उपन्यास जैसे मिथ्या पात्र कहे गये। सोनिया के प्रभुत्व वाली मनमोहन सरकार के इस शपथ पत्र ने कांग्रेस के अस्तित्व को ही काल चक्र के भंवर में उलझा कर डुबोना शुरू कर दिया। श्रीरामसेतु का अस्तित्व प्रमाणित होने से जितनी खुशी समाज में थी उससे कई गुना आक्रोश सारे भारत में खौल उठा। कांग्रेस और उसकी सहयोगी द्रमुक पार्टी की तमिलनाडु सरकार घुटनों पर आ गयी। न्यायालय ने श्रीराम रामसेतु तोड़ने पर रोक लगा दी। जनता ने कांग्रेस को वोट के बल से सत्ता से गिरा दिया। श्रीरामसेतु को देखने बड़ी समुद्री नौकाओं से पर्यटक मन्नार और रामेश्वरम की खाड़ी में पहुंचने का प्रयास करने लगे।

थोरियम की तस्करी और राजनीति : भारत के केरल, तमिलनाडु, ओडिसा और आंध्र प्रदेश के तटीय समुद्री भागों में संसार का सबसे बड़ा थोरियम खनिज भण्डार है। यह थोरियम वस्तुतः रेडियो धर्मी यूरेनियम का विकल्प ही नहीं ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। श्रीरामसेतु बन्ध को तोड़ने की जिद के पीछे यही थोरियम है। भारत से थोरियम की तस्करी कई दशकों से चीन के साथ ही यूरोप के कुछ देशों तक होती आ रही है। भारत से इस अति महत्वपूर्ण खनिज की तस्करी में कुछ राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं की संलिप्तता गम्भीर रहस्य है। भारत के पास संसार के कुल थोरियम का 25 प्रतिशत से ज्यादा भण्डार है। अन्यत्र एक साथ कहीं इतना बड़ा भण्डार नहीं है।

केरल के पूरे समुद्री तट में दूर तक थोरियम की चट्टानें हैं। श्रीराम सेतु के एक ओर मन्नार की खाड़ी है तो दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी है। बीच में श्रीरामसेतु की मोटी दीवार खड़ी है। तस्करी करने में लगे भारतीय

और विदेशी तस्कर चाहते हैं कि सेतुबन्ध की तीन किमी मोटी दीवार यदि बीच से काट कर चौड़ी नहर बना दी जाय तो भारतीय तटों का यह थोरियम जो निरन्तर चट्टानों से लहरों के थपेड़ों के कारण रेत बन कर जमा हो रहा है वह बहकर अन्तर राष्ट्रीय सीमा में पहुंचने लगे। अभी इसकी तस्करी कुछ भारतीय नेताओं के नियंत्रण में है जो बड़ी रकम चुकाने पर थोरियम ले जाने देते हैं। यह ऐसे नेता हैं जो तटीय केरल तमिलनाडु जैसे राज्यों में प्रायः सत्ता में बने रहते हैं। जिनमें कई नेताओं के अंतर राष्ट्रीय सम्बन्ध विदेशों में इसी तस्करी के चलते बहुत गहरे हैं।

थोरियम खनिज की महत्ता : एक किलोग्राम थोरियम से एक वर्ष तक निरन्तर 10000 घरों की सारी विद्युत ऊर्जा आवश्यकता की सम्पूर्ति की जा सकती है। थोतीयम रेडियो धर्मिता का यूरेनियम की तुलना में सुरक्षित स्रोत है। भारत की सरकारों ने अब तक समुद्र से इसे निकालने में रुचि नहीं ली। इसके पीछे उनके व्यक्तिगत स्वार्थ आड़े आते हैं। थोरियम की निकासी राष्ट्रीय स्तर पर होगी तो देश समृद्ध होगा। पर तब नेताओं का स्वार्थ पूरा नहीं होगा। इन नेताओं की दृष्टि में देश का हित कभी महत्व नहीं रखता। नरेन्द्र मोदी 2014 में सत्ता में आये तो तस्करी पर कड़ी निगरानी शुरू करायी। इससे हड़कम्प मचना ही था। बहुत से दलीय नेता मतभेद भुलाकर एकजुट हुए पर मोदी की दीवार वह तोड़ नहीं पा रहे। केरल तमिलनाडु के तटों से प्रतिमाह लाखों करोड़ का थोरियम बाहर जाता था। इसकी रुकावट से अन्तर राष्ट्रीय तस्करों के सशक्त गिरोह बेचैन हैं। इन तटों के दूरस्थ स्थलों से भारतीय नेवी सुरक्षा निगरानी कर रही है। शायद समय बीतने की प्रतीक्षा एक ओर भारत सरकार और दूसरी ओर अन्तर राष्ट्रीय तथा भारतीय तस्कर मिलकर कर रहे हैं। थोरियम सम्पदा के साथ श्रीसेतु समुद्रम का भाग्य सुनिश्चित होना है। देश में राष्ट्रवाद विजयी रहा तो श्रीसेतु समुद्रम का नया स्वरूप उभरेगा और थोरियम से भारत में ऊर्जा के नये सूर्य का उदय होगा। नहीं तो ब्राजील के तेल की तरह भारत के थोरियम की लूट मचेगी।

बच्चों के मानसिक विकास पर वायु प्रदूषण का मंडराता गंभीर खतरा



ज्ञानेन्द्र रावत
वरिष्ठ पत्रकार एवं पर्यावरणविद्

वायु प्रदूषण अब गंभीर जानलेवा समस्या बन गया है। हालात इस बात के सबूत हैं कि वायु प्रदूषण का असर अब हृदय, फेफड़ों, सांस, त्वचा, दमा, पाचनतंत्र से जुड़े रोगों को ही प्रभावित नहीं कर रहा है, हड्डियों, श्वसन प्रणाली, प्रजनन तंत्र से भी काफी आगे बढ़ गया है।

अब यह शरीर के हर अंग को प्रभावित कर रहा और अब यह कैंसर और मेटाबोलिक विकार को भी पार कर गया है। इससे मस्तिष्क पर भी गंभीर असर पड़ रहा है जिससे डिमेंशिया का खतरा बढ़ गया है। कारण अब वातावरण में मानक से भी ढाई गुणा ज्यादा प्रदूषक कण मौजूद हैं। अब तो यह इन रोगों के साथ मानसिक विकार के साथ-साथ बच्चों की बुद्धिमत्ता पर भी असर डाल रहा है। दुनिया के शोध-अध्ययन प्रमाण हैं कि वायु प्रदूषण बच्चों के मानसिक विकास के लिए गंभीर खतरा है। यह उनकी बुद्धिमत्ता, याददाश्त, एकाग्रता और उनके सीखने की क्षमता को कम करता है। प्रदूषित हवा में मौजूद सूक्ष्म कण बच्चों के दिमाग के विकास में बाधा डालते हैं जिसके परिणाम स्वरूप उनकी भाषा, कौशल, मूड नियंत्रण और व्यवहार सम्बंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उच्च वायु प्रदूषण और गंदी हवा में रहने वाले बच्चों के आई क्यू स्कोर में

मौजूद प्रदूषक तत्व बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन, उनकी सोचने-समझने की शक्ति-क्षमता और व्यवहार को सीमित कर देते हैं। यही नहीं अति सक्रियता विचार, खराब स्मृति और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई पैदा कर सकती है। यह स्थिति अवसाद और चिंता के जोखिम को और बढ़ा देती है। यातायात सम्बंधी वायु प्रदूषण इन समस्याओं की बढ़ोतरी में अहम भूमिका निभाता है।

एन पी जे क्लीन एयर नाम से प्रकाशित शोध में इस तथ्य का खुलासा हुआ है कि वायु प्रदूषण के कारण इंसान की सोचने-समझने की शक्ति आई क्यू भी प्रभावित हो रही है। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कुल 134 देशों में मौजूद 7800 से अधिक शहरों में



सेटेलाइट से सूक्ष्म कणों के लांग-लीनियर मॉडल के इस्तेमाल कर गणना की कि वायु प्रदूषण का आई क्यू पर कितना असर पड़ सकता है। वैज्ञानिकों ने अध्ययन के बाद कहा है कि हवा में मौजूद पी एम 2.5 (सूक्ष्म कण) की वजह से पूरी दुनिया की आबादी को 65 अरब आई क्यू अंक का नुकसान हो रहा है। उनके अनुसार पी एम कण इतने सूक्ष्म हैं कि वे शरीर के माध्यम से सीधे मस्तिष्क तक पहुंच रहे हैं। इससे दिमाग में आक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन पैदा हो रही है। धूल के इन कणों में कैडमियम, मैंगनीज और आर्सेनिक

जैसी जहरीली धातुएं होती हैं जो बच्चों के मानसिक विकास के लिए बेहद हानिकारक हैं। यह खतरनाक स्थिति है।

दरअसल वैज्ञानिकों ने यह शोध ईक्यू एक संख्या मानकर किया है जो यह बताती है कि किसी व्यक्ति की सोचने, समझने, तर्क करने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, उसकी उम्र के अन्य लोगों की तुलना में कितनी है। उन्होंने शोध में पाया कि हवा में मौजूद पी एम 2.5 के हर एक माइक्रोग्राम बढ़ने पर आई क्यू स्कोर में कितनी गिरावट आई है। वैज्ञानिकों के अनुसार प्रति व्यक्ति आई क्यू हानि का स्तर उन्नत देशों में ज्यादा है, जहां पी एम 2.5 का स्तर बहुत ज्यादा है। भारत में अत्याधिक प्रदूषण के कारण आई क्यू का नुकसान 20 अंक तक पहुंच गया है। कम और

मध्यम आय वाले देश इस संकट की सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं। इस दृष्टि से भारत में नुकसान ज्यादा है। शोध के अनुसार इससे बच्चों का विकास सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। यही नहीं सूक्ष्म कणों के असर से गर्भवती महिलाओं पर इसका ज्यादा खतरा है। गर्भावस्था के दौरान सूक्ष्म कणों का प्रभाव (1 से 6 अंक की हानि) या शराब के सेवन (3 से 7 अंक की हानि) जैसे स्थापित जोखिम कारकों के समान है। विकासशील देशों पर प्रदूषण की सबसे ज्यादा मार है। वहां यह नुकसान 19 अंक तक हो सकता है जबकि वैश्विक औसत 1 अंक से 2 अंक के बीच है। सबसे दुखदायी यह है कि 15 साल से कम उम्र के लगभग 2.02 करोड़ बच्चे इस प्रदूषण के शिकार हैं। इस बारे में चिकित्सकों की अभिभावकों को सलाह है कि वे अत्याधिक प्रदूषण की स्थिति में बच्चों को बाहर खेलने से रोकें। घर के अंदर एयर प्यूरीफायर का

इस्तेमाल करें और बाहर जाते समय मास्क लगायें।

हकीकत यह है कि वायु प्रदूषण से हर साल तकरीबन 20 लाख से ज्यादा लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज 93 फीसदी बच्चे प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। वायु प्रदूषण से जुड़ी होने वाली स्वास्थ्य समस्याएँ अक्सर एयरोसोल से जुड़ी होती हैं। एयरोसोल हवा में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल लवण होते हैं। इनका आकार कुछ नैनोमीटर से लेकर कई माइक्रोमीटर तक हो सकता है। एयरोसोल मानव आंखों को मुश्किल से दिखाई देते हैं। एयरोसोल में यह धुंआ, कोहरा और औद्योगिक प्रदूषण कण हैं। ये कण वायुमंडल में निलंबित धूल, समुद्री नमक, ज्वालामुखी की राख, धुंआ, पेड़ों से निकलने वाला रसायन और विभिन्न प्रकार के उत्सर्जन जैसे जीवाश्म ईंधन जलने यथा कारों और कारखानों से निकलने वाला प्रदूषण और औद्योगिक प्रदूषण आदि रूपों में पाया जाता है। यह जलवायु, मौसम और शरीर में विषाक्तता सम्बंधित प्रतिक्रियाओं को जन्म देते हैं। एयरोसोल रसायनों के चलते श्वसन सम्बंधी, लीवर, तंत्रिका तंत्र, आंख और त्वचा की समस्या पैदा होती हैं। इसके लम्बे समय तक संपर्क में रहने से फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। यहां तक कि इसके प्रभाव से पौधे और जानवर भी अछूते नहीं रह गये हैं। एयरोसोल के कण फेफड़ों में जलन पैदा कर सकते हैं और अत्याधिक सान्द्रता के कारण श्वसन तंत्र को अवरुद्ध भी कर सकते हैं। यहां तक कि यह मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं।

जहां तक देश की राजधानी दिल्ली का सवाल है, वह आज भी सबसे गंभीर वायु प्रदूषण का सामना करने को विवश है। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि यहां पी एम 2.5 का सालाना औसत आज भी सर्वाधिक है। चिंतनीय यह कि यहां पर गंभीर और आपात श्रेणी के वायु गुणवत्ता वाले दिनों की तादाद सबसे ज्यादा दिनों की अवधि तक बनी रहती है। हालात की भयावहता का जीता जागता

सबूत है दिल्ली विधान सभा में पिछले दिनों पेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें कहा गया है कि अभी प्रदूषण के मामले में दिल्ली में ढाई गुणा सुधार की जरूरत है। उसी दशा में दिल्ली वालों को सांस लेने लायक साफ हवा मिल सकेगी। दिल्ली विधान सभा की लोक लेखा समिति की रिपोर्ट भी राष्ट्रीय राजधानी में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने में सरकारी दावों की पोल खोलती है। उसके अनुसार प्रदूषण की निगरानी, सार्वजनिक परिवहन की बदहाली और उत्सर्जन मानकों

बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कुल 134 देशों में मौजूद 7800 से अधिक शहरों में सेटेलाइट से सूक्ष्म कणों के लांग-लीनियर मॉडल के इस्तेमाल कर गणना की कि वायु प्रदूषण का आई क्यू पर कितना असर पड़ सकता है। वैज्ञानिकों ने अध्ययन के बाद कहा है कि हवा में मौजूद पी एम 2.5 (सूक्ष्म कण) की वजह से पूरी दुनिया की आबादी को 65 अरब आई क्यू अंक का नुकसान हो रहा है।

को लागू करने में 'गंभीर प्रणालीगत खामियां' हैं। गौरतलब है यह रिपोर्ट कैंग द्वारा किए गये आडिट पर आधारित है। समिति ने परिवहन और पर्यावरण विभागों को इन खामियों को दूर करने के लिए तत्काल और समयबद्ध सुधारात्मक कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।

अब तो सर्दियों के दिनों में उत्तरी भारत के मुकाबले साफ माने जाने वाले देश के दक्षिणी राज्यों के प्रमुख शहर चेन्नई और बंगलुरु में वायु गुणवत्ता बिगड़ने के संकेत मिल रहे हैं जो एक खतरनाक नया जोखिम है। इसके पीछे मौसम को जिम्मेदार बताया जा रहा है। सीपीसीबी के एयर क्वालिटी मानीटरिंग डेटा पर आधारित संस्था क्लाइमेट

ट्रेंड्स के विश्लेषण की मानें तो मौसम की बदलती स्थितियां प्रदूषण के स्तर में 40 फीसदी तक बदलाव ला सकती हैं। देश के दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु, पटना, कोलकाता और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों के विश्लेषण से यह खुलासा हुआ है कि वायु प्रदूषण को केवल उत्सर्जन की समस्या मानना अधूरा दृष्टिकोण है। विश्लेषण के अनुसार वास्तव में उत्सर्जन और मौसम के बीच की परस्पर क्रिया ही वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करती है। उन हालात में जबकि हवा की गति कम और नमी ज्यादा होती है। तब वातावरण में ठहराव बनता है और प्रदूषण तेजी से बढ़ता है। इसलिए विभिन्न मौसमों को दृष्टिगत रखते हुए अलग-अलग लक्ष्यों का निर्धारण और मौसम आधारित कार्रवाई तंत्र विकसित करना बेहद जरूरी हो गया है।

असलियत में देश में अब वायु प्रदूषण केवल सर्दियों के मौसम का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि सालभर जारी रहने वाला गंभीर स्वास्थ्य खतरा बन चुका है। भारत में सभी श्वसन संबंधी मौतों में से एक तिहाई से अधिक वायु गुणवत्ता से जुड़ी हैं। इसके अलावा स्ट्रोक से होने वाली लगभग 40 फीसदी मौतों के लिए वायु प्रदूषण जिम्मेदार है। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायमूर्ति जायमाल्या बागची की आला पीठ ने सही ही कहा है कि वायु प्रदूषण की समस्या को अब सिर्फ सर्दियों की मुसीबत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। वायु प्रदूषण अब एक गंभीर समस्या का रूप ले चुका है। अब इसका फौरी निदान के बजाय दीर्घकालिक उपाय ढूंढना जरूरी हो गया है।

गौरतलब यह है कि शुद्ध हवा और शुद्ध पानी दोनों जीवन के अनिवार्य तत्व हैं। जाहिर है इनकी अनिवार्यता का कोई विकल्प नहीं है। इसके लिए संकीर्ण राजनीति और तंत्र की नाकामी जिम्मेदार है। इसे नकारा नहीं जा सकता। यहां इस सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता कि आज जब दुनिया के कई शहर प्रदूषण मुक्त हो चुके हैं और वहां की नदियां प्रदूषण मुक्त होकर कलकल बह रही हैं, उस दशा में हम क्यों नाकाम हो रहे हैं। यह चिंतनीय तो है ही, विचार का भी विषय है।

सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्सवों से भरपूर मई



नीलम भागी

लेखिका, जर्नलिस्ट, ब्लॉगर एवं ट्रेवलर



रू कूलों में छुट्टियां हो जाती हैं। हमारा कृषि प्रधान देश है। चरी, बाजरा बोकर, बाजरा में ग्वार लगा दी जाती है। इसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। इसलिए किसान के पास भी समय होता है और गर्मी भी उत्सवों की उमंग के साथ कटती है। कुछ त्यौहार तो पिछले महीने से चल रहे हैं। मई का महीना दक्षिण भारत के मंदिरों में वार्षिक ब्रह्मोत्सवम और रथ उत्सवों का समय होता है। केरल के कई मंदिरों में छोटे स्तर के 'पूरम' उत्सव भी इस दौरान आयोजित किए जाते हैं।

बुद्ध पूर्णिमा (1मई) वैशाख पूर्णिमा, सारनाथ मेला भारतीय बौद्ध सर्कट का महत्वपूर्ण स्थल होने के नाते, यहां एक विस्तृत मेले का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बौद्ध धर्मावलंबी यहां आते हैं। सागा दावा सिक्किम, दार्जीलिंग पर्यटन, वैशाख पूर्णिमा को यहां का प्रवास, स्थानीय लोगों को उनके सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार को मनाते हुए देखने और इस अनूठी संस्कृति, भव्य बौद्ध गतिविधियों को भी देखने का मौका मिलता है। कई प्रदेशों के बौद्ध बहुल क्षेत्रों में भगवान बुद्ध के जन्मोत्सव के रूप में इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह

भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण का प्रतीक है और उत्तर भारत में विशेष रूप से मनाया जाता है। 1 महीने तक चलने वाला चिथिराई महोत्सव, 19 अप्रैल से मदुरै तमिलनाडु के प्रसिद्ध मंदिर में भगवान सुंदरेश्वर के साथ, देवी मीनाक्षी के विवाह के उपलक्ष में मनाया जाता है। इस अवसर पर व्यापार, प्रदर्शनी, मेले आयोजित किए जाते हैं। 1 मई को भगवान कल्लाझगर का वैगई नदी में प्रवेश उत्सव का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण है। 2 मई को भगवान के 10 अवतारों की प्रदर्शनी तथा 3 मई को फूलों की पालकी में भगवान की विदाई यात्रा है।

मोआत्सु उत्सव (1 से 3 मई) यह नागालैंड की 'आओ' (Ao) जनजाति द्वारा मई के पहले सप्ताह में फसल बुवाई के बाद मनाया जाता है। इसमें पारंपरिक गीत और नृत्य के साथ प्रकृति का आभार व्यक्त किया जाता है। वैसे यह उत्सव सप्ताह तक चलता है।

अंतर्राष्ट्रीय पुष्प मेला गंगटोक (1 मई से 31 मई) सिक्किम में फूलों की सुंदरता और वृक्षारोपण के ज्ञान के साथ, स्वदेशी पौधों के बारे में व्याख्यान और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। क्षेत्रीय व्यंजनों के स्वाद के साथ, याक की सवारी का आनन्द

उठाया जाता है। जिन्हें रोमांच पसंद है, उनके लिए रिवर राफ्टिंग है।

नारद जयंती (2 मई) ऐसी मान्यता है कि नारद मुनि भगवान विष्णु के अवतार थे और सभी देवों के प्रिय थे। नारद जी तीनों लोकों में आया जाया करते थे। देवी-देवताओं और असुरों तक का संदेश पहुंचाया करते थे। हम इस दिन को पत्रकार दिवस के रूप में मनाते हैं।

ऊटी ग्रीष्म महोत्सव (4 से 27 मई में तक), नीलगिरी की ताजी हवा में प्राकृतिक सौन्दर्य के बीच, यह गर्मी के त्यौहार की तरह है। यहां फूलों की सजावट, सब्जियों की नक्काशी, फूलों की रंगोली, रोज शो, फ्रूट शो, डॉग शो, स्पाइस शो, वेजिटेबल शो, बोट शो का आनन्द उठा सकते हैं।

संकष्टी चतुर्थी 5 मई - भगवान गणेश को समर्पित व्रत है। 2026 में ज्येष्ठ माह में अधिकमास के कारण 19 साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसमें कुल 8 बड़े मंगल (बुढ़वा मंगल) पड़ेंगे। यह 5 मई से शुरू होकर 23 जून तक चलेंगे। हिंदू मान्यता के अनुसार, ज्येष्ठ माह के मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। बड़ा मंगल 5,12,19,26 मई को हैं।

बुढ़वा मंगल के दिन हनुमान जी के वृद्ध रूप की पूजा की जाती है। इस दिन हनुमान

चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है, जिससे मंगल दोष कम होता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। मंदिरों में भंडारे का आयोजन भी किया जाता है।

7 मई को रवींद्रनाथ टैगोर जयंती हैं, वहीं पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में यह उत्सव अक्सर बंगाली महीने बोइशाख के 25वें दिन, विश्वविख्यात कवि, संगीतकार, गीतकार निबंधकार और दार्शनिक रवींद्र नाथ टैगोर का जन्मदिवस मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रगान टैगोर जी की रचना की देन है। त्रिपुरा और असम के बंगाली समुदाय के बीच कवि रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई जाती है।

मातृ दिवस (10 मई) हिंदू धर्म में तो प्रत्येक दिन सुबह उठते ही मां को प्रणाम करने की परंपरा है। अब मई के दूसरे रविवार को बच्चे मां के लिए कुछ विशेष करते हैं। कैरियर के कारण घर से दूर रहना मजबूरी है। लेकिन अति व्यस्त रहने पर भी इस दिन को नहीं भूलते हैं और अपने अपने तरीके से मनाते हैं। यानि माताओं के सम्मान में मनाया जाने वाला आधुनिक उत्सव। अपरा एकादशी-13 मई) मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है।

हुंगरी मेला 14 से 16 मई घटोत्कच की माँ देवी हिडिम्बा के जन्मदिन के उपलक्ष में हुंगरी मेला लगाया जाता है। देवी हिडिम्बा का सम्मान करने के लिए क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण देवता आते हैं। इस उत्सव में भाग लेने के लिए स्थानीय देवताओं की रंग बिरंगी पालकियां भी मैदान में आती हैं।

ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू (14 से 16 मई) राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन पर असाधारण, दिलचस्प कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जो जुलूस के साथ शुरू होता है। उसके बाद राजस्थान, गुजरात के लोक प्रदर्शन शुरू होते हैं। फायरफ्लाइज़ त्योहार 14 मई से 21 जून को पुरुषवाड़ी में एक जादुई आयोजन है। प्रीमानसून सीजन के दौरान महाराष्ट्र के ग्रामीण शांत इलाकों में

हजारों जुगनु एक मनमोहक प्राकृतिक शो का निर्माण करते हैं। इस दौरान पर्यटकों के लिए तारों के नीचे कैम्पिंग, गाँव की सैर और कहानी सुनाने के सत्र शामिल किए जाते हैं। शनि जयंती और वट सावित्री व्रत 96 मई - शनि देव का जन्मोत्सव और सुहागिन महिलाओं द्वारा पति की लंबी आयु के लिए रखा जाने वाला व्रत, वट सावित्री रखा जाता है। इस दिन सौभाग्यवती महिलाएँ पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और संतान की कामना करते हुए व्रत करती हैं। वट यानि बरगद के पेड़ के नीचे बैठ कर व्रत की कथा करती हैं और उसकी पूजा करती हैं। शनि जयंती के कारण यह दिन शनि शांति पूजा के लिए भी महत्वपूर्ण है।

नारद जयंती (2 मई) ऐसी मान्यता है कि नारद मुनि भगवान विष्णु के अवतार थे और सभी देवों के प्रिय थे। नारद जी तीनों लोकों में आया जाया करते थे। देवी-देवताओं और असुरों तक का संदेश पहुंचाया करते थे। हम इस दिन को पत्रकार दिवस के रूप में मनाते हैं।

गंगा दशहरा (25 मई) माना जाता है कि इसी दिन माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। उत्तर भारत (विशेषकर ऋषिकेश, हरिद्वार और वाराणसी) में इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान, दान और जल सेवा का विशेष महत्व माना जाता है। पद्मिनी एकादशी एवं गायत्री जयंती (अधिक मास एकादशी-27 मई) अधिक मास में आने वाली एकादशी विशेष पुण्यदायी मानी जाती है। गायत्री परिवार के लिए वर्ष 2026 एक अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि इसे स्वर्णिम शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान शांति कुंज,

हरिद्वार और विश्व भर में कई आध्यात्मिक कार्यक्रमों और महायज्ञों की श्रृंखला आयोजित करने की योजना है।

वीर सावरकर जयंती, (28 मई) भारत के क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाजसुधारक, इतिहासकार, विचारक थे। ईगितुन चालने (आग में चलना) सिरिगाओ गोवा, यह राजधानी पणजी से 30 किमी दूर, सिरिगाओ के मंदिर में मनाया जाता है। अनुष्ठान देखने के लिए आगंतुक और स्थानीय लोगों की भीड़ मंदिर के चारों ओर लग जाती है।

• ज्येष्ठ पूर्णिमा (30 मई) - धार्मिक स्नान और दान-पुण्य के लिए महत्वपूर्ण तिथि है।

• सागा दावा (31मई) सिक्किम में यह पवित्र महीना मई-जून के आसपास पड़ता है। 2026 में मई के अंत तक इसके मुख्य धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो सकते हैं, जो बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को समर्पित हैं। येरकोंड ग्रीष्मोत्सव सलेम तमिल नाडु में मई के अंतिम सप्ताह अन्ना पार्क में फूलों की प्रदर्शनी, नाव दौड़, सांस्कृतिक आयोजन, डॉग शो, गांव के दौरे, साहासिक गतिविधियों के साथ पर्यटन का जश्न मनाया जाता है। यहां हर साल, त्योहार के दौरान आयोजनों की गतिविधियां बदल जाती हैं। इसलिए इस उत्सव में मौज मस्ती और जश्न की गारंटी मानी जाती है।

ऐसे में विविधताओं के हमारे देश में महापुरुषों के जन्मदिवसों, कहीं मौसम के कारण प्रकृति की सुन्दरता और धार्मिक शुभ दिनों के कारण मेले, उत्सव होते हैं। जिससे जीवन की एकरसता दूर होती है। उस दिन क्या पारंपरिक पकवान बनेंगे? लाल, पीले आदि खिले हुए रंगों की पोशाकों का उत्सवों में पहनने का जिक्र चलता है और उस विशेष दिन से संबंधित कथाएं सुनने को मिलती हैं। बजट के अनुसार पर्यटन की योजना बनाना और फिर तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इससे सामाजिक समरता बढ़ती है।

मुरादाबाद में शुरू हुआ निःशुल्क बुक बैंक



मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश : समाज की उन्नति में शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और यह केवल सरकार ही नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी भी है कि वह शिक्षा को बढ़ावा देने में अपना योगदान दे। मुरादाबाद नगर निगम ने शिक्षा को बढ़ावा देने और गरीब

बच्चों की सहायता के लिए बुक बैंक शुरू किया है। इस बुक बैंक में जरूरतमंद छात्र-छात्राओं को निःशुल्क में किताबें दी जा रही हैं। इसका उद्देश्य उन बच्चों की सहायता करना है, जो पैसे की कमी के कारण किताबें नहीं खरीद पाते। इस बुक बैंक में स्कूल, कॉलेज और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी कई तरह की किताबें उपलब्ध हैं। छात्र अपनी आवश्यकता के अनुसार यहां से किताबें लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। बुक बैंक में काम करने वाले अमरीश शर्मा ने बताया कि ये किताबें लोग खुद दान में देकर जाते हैं। फिर इन किताबों को जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाया जाता है। यहां लगभग हर विषय की किताब मिल जाती है। नगर निगम और नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल का प्रयास है कि कोई भी बच्चा आर्थिक परेशानी के कारण पढ़ाई से पीछे न रह जाए। इस पहल से कई बच्चों को लाभ मिल रहा है। यह बुक बैंक सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित है, जहां शहर और गांव दोनों जगहों के बच्चे आकर निःशुल्क में किताबें ले सकते हैं। इससे उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिल रहा है।

प्रकृति, परंपरा और रोजगार का संगम-छाती मनकोट

छाती मनकोट गांव उत्तराखण्ड का एक छोटा लेकिन प्रेरणादायक गांव है, जहां लोगों ने अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पारंपरिक पहाड़ी खानपान को रोजगार का माध्यम बना लिया है। अगर आप उत्तराखण्ड घूमने जाएं और वहां की खूबसूरत वादियों के साथ-साथ स्थानीय स्वाद भी चखने को मिल जाए, तो सफर सच में यादगार बन जाता है। छाती मनकोट गांव ऐसा ही एक खास गांव है, जो बागेश्वर जिले में स्थित है। पहाड़ों की गोद में बसा यह छोटा सा गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सादगी भरी जीवनशैली के लिए जाना जाता है। ऊंची-नीची पहाड़ियां, घने जंगल और शांत वातावरण यहां आने वाले हर यात्री को अपनी ओर खींच लेते हैं। यह गांव पिथौरागढ़ को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, जहां से रोज बड़ी संख्या में यात्री गुजरते हैं। अब गांव वालों ने इस मौके को रोजगार में बदल दिया है। यहां पहुंचते ही यात्रियों का स्वागत होता है पहाड़ के पारंपरिक स्वाद से चूल्हे पर बनती भट्ट की दाल और मंडुवे की रोटी की सोंधी खुशबू हर किसी को रुकने पर मजबूर कर देती है। प्राकृतिक तरीके से तैयार किया गया यह भोजन न सिर्फ स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। यही वजह है कि पर्यटक यहां रुककर पहाड़ की असली जिंदगी को करीब से महसूस कर रहे हैं। धीरे-धीरे इस गांव में होमस्टे संस्कृति भी



विकसित हो रही है, जिससे पर्यटकों को स्थानीय जीवनशैली को जानने का मौका मिल रहा है और गांव वालों को अपने ही गांव में रोजगार मिल रहा है। आज छाती मनकोट सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि प्रकृति, संस्कृति और आत्मनिर्भरता का एक सुंदर उदाहरण बनता जा रहा है। यह पहल दिखाती है कि अगर स्थानीय संसाधनों का सही प्रयोग किया जाए, तो छोटा सा गांव भी बड़ा पर्यटन केंद्र बन सकता है और पलायन जैसी समस्या को भी रोका जा सकता है।

गोबर से स्वावलंबन की नई कहानी



एक समय था जब गोबर से घर लीपे जाते थे और इसे सबसे शुद्ध माना जाता था। आज भी इसकी उपयोगिता कम नहीं हुई है, बस नजरिया बदलने की जरूरत है। जहां कुछ लोग इसे देखकर नाक सिकोड़ते हैं, वहीं उत्तराखण्ड के काशीपुर के एक युवा ने इसी गोबर को अपने कौशल से सफलता की सीढ़ी बना दी। यह हैं नीरज चौधरी-जिन्होंने गोबर से स्वावलंबन की एक नई राह तैयार की है। बीटीसी, टीईटी और एमएसडब्ल्यू (मास्टर ऑफ सोशल वर्क) की पढ़ाई करने वाले नीरज को एक विदेशी पुस्तक "The Devil in the Milk" से प्रेरणा मिली। इसके बाद उन्होंने देसी गायों का पालन शुरू किया और वर्ष 2017 से गोबर से उत्पाद बनाने का काम आरंभ किया। शुरुआत लक्ष्मी-गणेश की पारंपरिक मूर्तियों से हुई, जो लगभग 400 रुपये तक बिकती थीं। धीरे-धीरे उन्होंने अपने उत्पादों की

विविधता बढ़ाई- चाबी के छल्ले, दीये, दीवार घड़ियां, मूर्तियां, डिजिटल फोटो और 3D मॉडल तक बनाने लगे। आज उनके द्वारा बनाए गए लक्ष्मण झूला, बैलगाड़ी, श्रीराम मंदिर और 150 किलो का श्रीयंत्र काफी लोकप्रिय हैं। उनका बनाया 6 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा केदारनाथ धाम मंदिर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। यह केवल उत्पाद नहीं हैं, बल्कि नए भारत के युवाओं की बदलती सोच का प्रतीक हैं। नीरज के बनाए गोबर उत्पाद प्रधानमंत्री तक को भेंट किए जा चुके हैं, जिनकी नीलामी करीब 3 लाख रुपये तक पहुंची।

अपने उत्पादों में नीरज 80-90 प्रतिशत तक गोबर का उपयोग करते हैं। इसे मजबूती देने के लिए वे प्राकृतिक सामग्री जैसे ग्वार गम (प्राकृतिक गोंद), मुल्लानी मिट्टी, चूना, मैदा और लकड़ी का उपयोग करते हैं। उनके इस प्रयास को देखते हुए काशीपुर नगर पालिका ने उन्हें ब्रांड एंबेसडर भी नियुक्त किया है। अब तक वे करीब 10,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दे चुके हैं, जिससे कई परिवारों को रोजगार और आत्मनिर्भरता मिली है। काशीपुर के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ यह प्रयास आज अनेक लोगों के जीवन में आर्थिक मजबूती और आत्मविश्वास भर रहा है। यही है आत्मनिर्भर भारत की असली तस्वीर - जहां कौशल है, संकल्प है और खुद पर विश्वास है। अपने आसपास के संसाधनों को पहचानिए, उन्हें अवसर में बदलिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दीजिए। क्योंकि जब हर गांव आत्मनिर्भर बनेगा, तभी भारत सशक्त और समर्थ बनेगा।

बेसहारा लोगों को अंतिम सम्मान की प्रेरणादायक पहल

समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें जीवन में सहारा नहीं मिल पाता, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उन्हें सम्मान देना भी हमारा कर्तव्य है। फिरोजाबाद में इसी सोच के साथ एक सराहनीय और मानवीय पहल की जा रही है, जो समाज के लिए प्रेरणा बन रही है। जी हां, फिरोजाबाद में लावारिस और बेसहारा लोगों को उनकी मृत्यु के बाद सम्मानजनक अंतिम विदाई देने का कार्य किया जा रहा है। इस पहल के तहत उनकी अस्थियों को पूरे विधि-विधान से गंगा में विसर्जित किया जाता है, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके।

इस नए काम की शुरुआत कई साल पहले एक संत ने की थी। अब 'बैकुंठ धाम वेलफेयर ट्रस्ट' के सदस्य इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। संस्था पिछले 5 वर्षों से लगातार इस कार्य को कर रही है। संस्था के संचालक जितेंद्र शर्मा के अनुसार, लावारिस व्यक्तियों का अंतिम संस्कार बैकुंठ धाम में विधिपूर्वक किया जाता है। इसके बाद उनकी अस्थियों को सुरक्षित रखा जाता है और जब पर्याप्त संख्या में अस्थियां

इकट्ठी हो जाती हैं, तो उन्हें सोरों गंगा घाट ले जाकर विधि-विधान से विसर्जित किया जाता है।

अब तक 250 से अधिक लोगों की अस्थियों का विसर्जन किया जा चुका

है। इस पूरे कार्य में संस्था के सदस्य अपने निजी खर्च से सहयोग करते हैं। गंगा में अस्थि-विसर्जन के बाद मृत आत्मा की शांति के लिए गरुड़ पुराण का पाठ भी कराया जाता है। यह पहल हमें यह सिखाती है कि समाज के प्रति हमारा कर्तव्य केवल जीवित लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमें उन लोगों के लिए भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए जो जीवन में अकेले रह गए। यह एक ऐसा कार्य है, जो मानवता, संवेदनशीलता और संस्कारों की सच्ची प्रेरणा प्रस्तुत करता है।



देसी खुशबू, विदेशी पहचान : बरेली के चावल की दुनिया में धूम



बरेली, जिसे अब तक सिर्फ “झुमका गिरा रे” के लिए जानते थे। अब वही बरेली दुनिया के किचन में अपनी खुशबू फैलाने जा रहा है। यहां के ‘झुमका बासमती’ और ‘तिलक चंदन’ चावल अब लंदन तक पहुंच चुके हैं और ग्लोबल मार्केट में छा रहे हैं। लंदन में हुई इंटरनेशनल फूड एग्जिबिशन। जहां दुनिया भर के फूड ब्रांड्स ने अपनी ताकत

दिखाई। वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली ने भी दमदार एंट्री मारी। गाडसन ऑर्गेनिक फार्म के ‘झुमका बासमती’ और ‘तिलक चंदन’ जैसे सुगंधित चावल अपनी खुशबू और क्वालिटी से विदेशी खरीदारों का दिल जीतते नजर आए। इतना ही नहीं, स्पाइस विस्ता कर्पोरेशन की लाल मिर्च और पीली मिर्च भी अपने नैचुरल रंग, खुशबू और बैलेंस्ड तीखेपन के चलते ग्लोबल खरीदारों को खूब पसंद आई। स्पाइस विस्ता कारपोरेशन के आकाश अग्रवाल का कहना है कि हमने पूरी प्रोसेसिंग को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ा है, ताकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की क्वालिटी दे सकें।

महिलाओं को मिला सुरक्षित सफर और रोजगार का नया अवसर

उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। जी हां, ‘सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम’ के माध्यम से अब महिलाएं स्वयं ई-रिक्शा चलाकर न केवल अपनी कमाई कर रही हैं, बल्कि दूसरी महिलाओं को सुरक्षित सफर भी दे रही हैं। योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ‘सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम’ शुरू किया है। इस योजना के तहत महिलाओं को ई-रिक्शा दिए जा रहे हैं, जिन्हें वे स्वयं चलाएंगी। इससे छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित यात्रा की सुविधा मिलेगी। पहले चरण में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को 1000 ई-रिक्शा दिए जा रहे हैं। अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, कौशांबी और झांसी में यह योजना शुरू हो चुकी है। जल्द ही लखनऊ, प्रयागराज, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, देवरिया, लखीमपुर खीरी और सीतापुर में भी इसे लागू किया जाएगा। इस योजना से महिलाओं को बड़ा लाभ हो रहा है। अब तक 119 महिलाओं को ई-रिक्शा देकर उन्हें रोजगार मिला है। 629 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है और 244 महिलाएं ड्राइविंग लाइसेंस भी प्राप्त कर चुकी हैं। इससे जुड़ी महिलाओं की सालाना औसत आय 3 लाख रुपये से अधिक हो गई है। यह पहल केवल रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब महिलाएं महिला ड्राइवर के साथ सुरक्षित महसूस करती हैं। गांवों में बेटियों का स्कूल जाना आसान हुआ है और कामकाजी महिलाओं को भरोसेमंद यात्रा का विकल्प मिला है। कुल मिलाकर, यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रही है।



सरिता पपोला बर्नी महिला सशक्तिकरण की प्रेरणा



पहाड़ की संकरी गलियां और इन गलियों में दौड़ती एक स्कूटी जिस पर बैठी हैं सरिता पपोला, जो अब बागेश्वर की पहचान बन चुकी हैं। कभी सरिता का दिन घर की जिम्मेदारियों और बच्चों की परवरिश में ही बीतता था। लेकिन मन में कुछ अलग करने का सपना भी था। अपने सपने को सच करने के लिए सरिता ने एक एनजीओ से जुड़कर काम शुरू किया। यहीं से उन्हें बाहरी दुनिया की समझ मिली और आत्मविश्वास

भी बढ़ा। फिर आया वो फैसला, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। डिलीवरी वुमन बनने का फैसला। शुरुआत आसान नहीं थी लेकिन हौसले के आगे हर मुश्किल छोटी पड़ गई। सरिता की इस सफलता के पीछे उनके परिवार का भी बड़ा योगदान है। उनके पति, जो पेशे से वकील हैं। हर कदम पर उनके साथ खड़े रहे। आज सरिता बिना किसी झिझक के घर-घर सामान पहुंचा रही हैं और साथ ही यह संदेश भी दे रही हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। बागेश्वर की इन गलियों में अब सरिता सिर्फ एक डिलीवरी वुमन नहीं, बल्कि समाज परिवर्तन की पहचान बन चुकी हैं। उनकी कहानी हर उस महिला के लिए प्रेरणा है, जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहती है।

अचार बनाकर लिख रही कामयाबी की कहानी

मेरठ के पांचली खुर्द गांव में रुद्रा सहायता समूह की महिलाओं द्वारा एक नहीं बल्कि 30 से अधिक वैरायटी के अचार बनाकर तैयार किए जाते हैं। समूह की पदाधिकारी दुर्गेश ने सर्वप्रथम मेरठ के राजकीय खाद एवं विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र से अचार बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत डेढ़ लाख रुपए के लोन की मदद लेकर अचार के बिजनेस की शुरुआत की। उन्नति उत्पाद नाम से यूनिट की शुरुआत की। एमएसएमई एवं फूड लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात मार्केट में अपना अचार बिक्री के लिए उतारा। 8 महीने में ही समूह द्वारा तैयार किए गए अचार की डिमांड आस-पास के क्षेत्र में है। उनके पास मिर्च, मूली, गाजर, करेला, कटहल, गोभी, नींबू

के आचार और सेब, आंवले के मुरब्बे सहित 30 प्रकार के अचार मौजूद हैं। सभी अचार समूह द्वारा ऑर्गेनिक पद्धति से ही तैयार किए जाते हैं। इसके लिए सभी मसाले को इमाम दस्ते में कूटने के बाद ही उनका उपयोग किया जाता है। समूह की प्रत्येक महिला को उन्नति उत्पादन यूनिट और रुद्र स्वयं सहायता समूह के नाम से जाना जाने लगा है।



बीसी सखी से शुरू हुआ सफर बना कारोबार



बुलंदशहर के सिकंदराबाद के भराला गाँव की दीपमाला का बीसी सखी से शुरू हुआ सफर कारोबार तक पहुंच गया है। आज बीसी सखी दीपमाला नारी सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रही हैं। जब इनका परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था तो दीपमाला छह वर्ष पूर्व राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ीं और बीसी सखी बनकर आस-पास की महिलाओं को बचत कराई और अपने साथ जोड़कर एक समूह का गठन कर रिवोल्विंग फंड का लाभ उठाया। आज समूह की महिलाएं अचार-मुरब्बा, चिप्स-पापड़ खाद्य पदार्थों का उत्पादन कर अपने जीवन को नई दिशा दे रही हैं। समूह से जुड़ी महिलाएं ब्यूटी पार्लर, सिलाई कढ़ाई और भैंस पालन भी कर रही हैं, अपनी-अपनी रुचि के अनुसार काम करके अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर रही हैं। अपने गाँव देहात से जुड़कर उन्होंने गाँव में ही अपने विकास के लिए अवसर खोज लिए हैं।

खेत को बनाया प्रयोगशाला, मरणोपरांत मिलेगा पद्मश्री सम्मान

मुरादाबाद के समथल गाँव के किसान स्वर्गीय रघुपत सिंह ने एक अनूठा उदाहरण किसानों के सामने रखा। उन्होंने देखा कि किसानों को हर बार अपनी फसल के लिए नए बीज खरीदने पड़ते हैं, तब उन्होंने भारत की बीजों को सुरक्षित एवं संवर्धित करने की लुप्त होती जा रही परम्परागत तकनीक को अपनाया और अपने ही खेत में बीजों के प्रसंस्करण को लेकर प्रयोग किये। उनके अथक परिश्रम से उन्होंने वह कर दिखाया जो क्षेत्र के किसानों के लिए मिसाल बन गया। रघुपत जी गाँवों के विकास को ही देश की सम्पन्नता का मूल मन्त्र मानते थे। उन्होंने सीमित जमीन में नवाचार के द्वारा आने वाली पीढ़ियों के लिए बीजों को संरक्षित करने के लिए अपना जीवन लगा दिया। उन्होंने अपनी जीवन साधना से बीजों की उन्नत किस्में तैयार की। जिनमें प्रमुख हैं रु कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली उड़क की 'अलंकार' प्रजाति, अरहर

की नामीबिया मूल की प्रजाति को स्थानीय जलवायु में ढाला, बेहतर दाना और उत्पादन क्षमता वाली राजमा की कई स्थानीय किस्में, पांच



फीट लंबाई वाली लौकी की प्रजाति, एक मीटर तक लंबी लोबिया की फलियां, एक ही पौधे पर वर्षों तक फल देने वाली मिर्च, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली देशी भिन्डी और करेला, बेल पर उगने वाली अरबी, विशेष स्वाद वाली अदरक। बिना किसी विश्वविद्यालयी अध्ययन के वे एक कृषि वैज्ञानिक ही थे। उनके योगदान को देखते हुए सरकार द्वारा उन्हें मरणोपरांत पद्म श्री से सम्मानित किया जायेगा।

कुलदेवता

-बालेश्वर गुप्ता

ज दादी अम्मा की आंखों में अलग ही चमक दिखायी दे रही थी।
आ नम होती आंखों को बार बार पोछती और सामने लगे पीपल के वृक्ष पर कलावा बांधते बांधते दादी अम्मा भावुक हो उठती। मम्मी शायद दादी की भावनाओं को समझ रही थी तभी तो बार बार वे दादी अम्मा को सहारा भी देती और उनका सहयोग भी कर रही थी।

पता नहीं कब, कुछ किसी को कुछ याद तक नहीं कि घर के सामने हमारे ही किस पीढ़ी के पूर्वज ने एक पीपल का पेड़ लगाया था और वहीं एक बहुत छोटा सा त्रिकोण सा ईंटों का एक मंदिर नुमा ढांचा बनवा दिया था। सब कहते कि वहां हमारे कुल देवता निवास करते हैं और पीपल का वृक्ष उन पर छाया रखता है। यूँ तो हमारे घर से कोई न कोई प्रतिदिन कुलदेवता के घर में दीपक जलाता ही था, पर यदि घर में कोई बीमार पड़ जाता या कोई परेशानी खड़ी हो जाती तो कुलदेवता को खूब याद किया जाता और तब वहां वह संकट टलने तक दादी अम्मा स्वयं ही रोज दीपक जलाती और पीपल पर कलावा बांधती। उनका विश्वास था कि हमारे कुलदेवता जरूर हमारी सहायता करेंगे। मेरे पापा ने तो कुलदेवता के उस घर को टाइल्स से सजवा दिया था तथा पीपल के उस वृक्ष के चारों ओर चबूतरा बनवा दिया था। उस चबूतरे पर गांव के लोग भी रोज बैठ कर अपनी महफिल देर रात तक जमाते थे, मेरे पापा भी उनके साथ ही बैठते। पीपल का वह पेड़ असल में मेरे परिवार की भावनाओं से तो जुड़ा ही था, वह गांव की पहचान भी बन गया था। राम कृपाल जी की अपनी पैतृक हवेली गांव में जहां स्थित थी उसी के पीछे उनकी कई एकड़ कृषि भूमि भी थी और सामने था पीपल का पेड़। रामकृपाल जी तो स्वर्ग सिंघार गये थे पर पीपल के पेड़ के नीचे बने कुलदेवता पर दीपक जलाने और पीपल पर कलावा बांधने की परंपरा जो परिवार में चली आ रही थी उसे उन्होंने बड़ी ही श्रद्धा से चालू रखा था। उसी परंपरा का निर्वहन अब उनका पुत्र रमेश और उसकी पत्नी कर रहे थे। इनका एक मात्र पुत्र मुन्ना जो मुश्किल से 7-8 वर्ष का ही था, वह भी यह सब कौतूहल पूर्वक देखता था या यूँ कह ले वह भी भविष्य के लिये इस परंपरा को चलाने की ट्रेनिंग ले रहा था। राम कृपाल जी की पत्नी यानि रमेश की माता जी यानि मुन्ना की दादी यशोदा 87 वर्ष की अवस्था में भी कुलदेवता पर दीपक जलाना और पीपल के वृक्ष पर कलावा बांधने को नहीं भूलती। कोई न हो तो भी वे मुन्ना का हाथ पकड़ कर पीपल के पेड़ के नीचे चली आती।

एक वज्रपात एक दिन हो गया। सरकार का फरमान आ गया कि इधर से एक सड़क निकलेगी और वह पीपल का वृक्ष वहां से उखाड़ दिया जायेगा। पूरे घर में मातम छा गया। क्या हमारे

कुलदेवता को हटा दिया जायेगा, हमारी पहचान बन चुके पीपल के पेड़ को भी हटा दिया जायेगा? सोचकर ही घर के पूरे सदस्य सदमे में आ जाते। रमेश जी खुद अंदर से दुखी थे, पर असहाय अवस्था में माँ को समझाते, माँ तू ही बता, कुलदेवता तो हमारे मन में बसे हैं, गांव का विकास हो रहा है, शहर के लिये सड़क बन रही है तो क्या हम रोड़ा बन जायें? माँ कुछ न बोल पाती, पता नहीं विकास की बात वह समझ भी रही है या नहीं, बस उसकी आंखों से आंसू ढलक पड़ते। असल बात तो यह थी सब दुखी थे, पर आत्मसंतुष्टि का कोई न कोई तर्क गढ़ते, पर सफल कोई नहीं हो रहा था, सब एक दूसरे से आंख बचा रहे थे।

बेचैन से रमेश जी को एक उपाय सूझा और वे अगले दिन शहर में जिलाधिकारी महोदय से अकेले ही मिलने पहुंच गये। जिलाधिकारी महोदय को उन्होंने अपनी 87 वर्षीय माँ की भावनाओं का हवाला देते हुए प्रस्ताव रखा कि निर्माण होने वाली सड़क के लिये वे बिना किसी मुहवाजे के अपने खेत की भूमि देने को तैयार हैं। बस हमारे पीपल के वृक्ष को सुरक्षित छोड़ दिया जाये।

जिलाधिकारी महोदय आश्चर्य से रमेश के चेहरे को देख रहे थे। एक पीपल के वृक्ष के लिये जिससे किसी फल तक भी प्राप्ति नहीं होती यह व्यक्ति अपनी कृषि भूमि भी देने को तैयार है, बस इसलिये कि उस पीपल के पेड़ के नीचे उनके कुलदेवता वास करते हैं। जिलाधिकारी महोदय यह भी सोच रहे थे कि काश आज भारत में हर पेड़ के नीचे किसी न किसी के कुलदेवता का वास होता तो कोई पेड़ कटता ही नहीं, पर्यावरण की समस्या से जूझना ही नहीं पड़ता। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बुलाकर रमेश जी के प्रस्ताव पर विचार करने के निर्देश दिये। पीडब्ल्यूडी अधिकारी बोले साहब वह सड़क वास्तव में सुविधानुसार रमेश जी के खेत से ही निर्मित होनी थी, पर कृषि भूमि होने के कारण उसकी उपलब्धता न होने की दशा में परियोजना विलंबित होती इसलिये ही सड़क के निर्माण के लिये पीपल के वृक्ष वाली राह को चुना गया था। विभाग तो रमेश जी को उचित मुहवजा भी देने को तत्पर है। रमेश जी तो हतप्रभ रह गये। उनके प्रस्ताव को इतनी सहजता से स्वीकार कर लिया जायेगा, इसकी तो उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। घर वापस आ रमेश जी अतिरिक्त में दरवाजे से चिल्ला रहे थे, माँ ओ माँ देख तो अपने कुलदेवता की महिमा, माँ अब हमारे भगवान कही नहीं जायेंगे, हमारा पीपल यूँ ही फैलता रहेगा। माँ की आंखों में आंसू तो आज भी थे, पर ये आंसू उनकी श्रद्धा और विश्वास की जीत के थे।



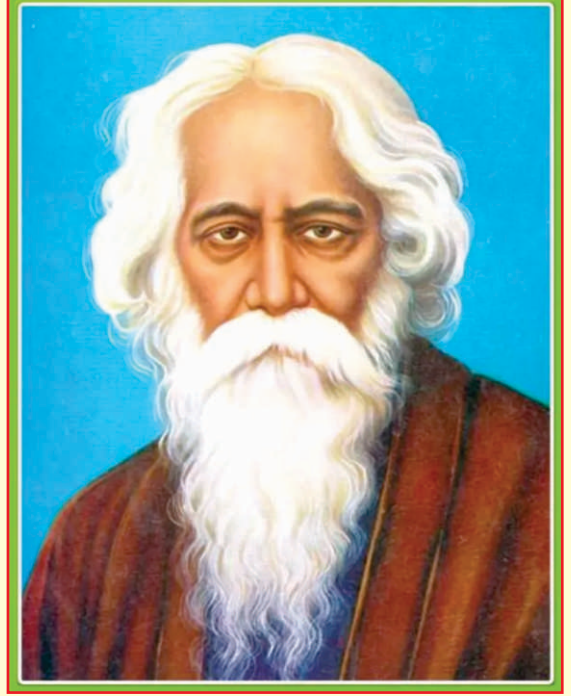
विश्व कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर

बां ग्ला और अंग्रेजी साहित्य के माध्यम से भारत को विश्व रंगमंच पर अमिट स्थान दिलाने वाले रवीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म सात मई, 1861 को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवेन्द्रनाथ तथा माता का नाम शारदादेवी था। बचपन से ही काव्य में रुचि रखने वाले इस प्रतिभाशाली बालक को देखकर कौन कह सकता था कि एक दिन विश्वविख्यात नोबेल पुरस्कार जीतकर यह कवि भारत का नाम दुनिया में उज्ज्वल करेगा।

रवीन्द्रनाथ के परिवार में प्रायः सभी लोग विद्वान थे। इसका प्रभाव उन पर भी पड़ा। उन्होंने लेखन की प्रायः सभी विधाओं में साहित्य की रचना की। एक ओर वे कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि में सिद्धहस्त थे, तो दूसरी ओर वे उच्च कोटि के चित्रकार, संगीतकार, दार्शनिक व शिक्षाशास्त्री भी थे। उन्होंने अपनी सभी कविताओं को शास्त्रीय संगीत में निबद्ध भी किया है। सोनार तरी, पुरवी, दि साइकिल ऑफ स्प्रिंग, दि ईवनिंग सांग्स और मार्निंग सांग्स उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। उनके लेखन का विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद हुआ है तथा आज भी लगातार उन पर काम हो रहा है।

1913 में गीतों की पुस्तक 'गीतांजलि' पर उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। आज भी ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा, कला, साहित्य आदि क्षेत्रों में यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। रवीन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे, जिन्हें इस सम्मान से अलंकृत किया गया। उन्होंने गौरा, राजरानी, घरे-बाहिरे, विनोदिनी जैसे प्रसिद्ध उपन्यास भी लिखे। चित्रा उनका प्रसिद्ध गीतनाट्य है। उनकी कहानी काबुलीवाला पर इसी नाम से एक फिल्म भी बनी, जिसे देखकर आज भी दर्शकों की आँखें भीग जाती हैं।

रवीन्द्रनाथ शिक्षा को देश के विकास का एक प्रमुख साधन मानते थे। इस हेतु उन्होंने 1901 में बोलपुर में 'शान्ति निकेतन' की नींव रखी। यहाँ प्राचीन भारतीय परम्पराओं के साथ ही पश्चिमी शिक्षा का तालमेल किया गया है। नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद 1921 में उन्होंने शान्ति निकेतन में



ही 'विश्व भारती विश्वविद्यालय' की स्थापना की। इसमें विश्व भर के छात्र पढ़ने आते थे। आज भी यहाँ के प्राकृतिक और शान्त वातावरण में पढ़ने वाले छात्रों में सहज ही कला के संस्कार विकसित हो जाते हैं।

विश्व भारती की स्थापना के बाद उन्होंने देश-विदेश का सघन प्रवास किया। वे चाहते थे कि इस विद्यालय में न केवल विश्व भर के छात्र अपितु विद्वान् अध्यापक भी आर्यें, जिससे उनके ज्ञान का सबको लाभ मिल सके। उनका यह प्रयास सफल रहा और आज भी वहाँ यह परम्परा विद्यमान है। उनके जीवनकाल में ही वहाँ कला भवन, संगीत भवन, शिक्षा भवन, श्रीनिकेतन, चीन भवन, शिल्प भवन और हिन्दी भवन की स्थापना हो गयी थी। 1915 में अंग्रेजी शासन ने उन्हें 'सर' की उपाधि से विभूषित किया; पर 1919 में जलियाँवाला बाग कांड के विरोध में उन्होंने इसे वापस कर दिया।

भारत का वर्तमान राष्ट्रगान 'जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता..' उनका ही रचा हुआ है। गांधी जी उन्हें सम्मानपूर्वक 'गुरुदेव' कहकर पुकारते थे। जीवन भर साहित्य की सेवा और साधना करते हुए 1941 में कोलकाता में ही रवीन्द्रनाथ टैगोर का देहान्त हो गया।



Nirala Gateway

📍 Sector 12, Greater Noida (W).



RETAIL

OFFICE

STUDIO APARTMENTS



Project Id: (UPRERAPRJ531916/06/2025)
Registration Date: 17-06-2025
Promoter Name: Parth BUILTECH Private Limited
Promoter Id: (UPRERAPRM348231)
Website: <https://www.up-rera.in/projects>